लखनऊ

बुधवार, 29 अप्रैल, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 246

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

"पढ़ाई में ध्यान लगाने का सबसे अच्छा तरीका है अपना लक्ष्य रोज़ याद करो और खुद को उसी दिशा में धकेलो।"

TODAY WEATHER

DAY 42° Hi

NIGHT 26° Low

संक्षेप

लीबिया में भारतीय कंपनियों को तेल और गैस का नया भंडार मिला: पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली। भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने आधिकारिक एक्स पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि लीबिया में भारतीय कंपनियों को तेल और गैस का नया भंडार मिला है। मंत्रालय के अनुसार, यह खोज लीबिया के गदामेस बेसिन में कॉन्ट्रैक्ट एरिया 95/96 में की गई है। इस प्रोजेक्ट में ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारतीय कंसोर्टियम पार्टनर हैं, जबकि अल्जीरिया की कंपनी सिपेक्स (एसआईपीएक्स) इस प्रोजेक्ट की ऑपरेटर है। बताया गया है कि इस कुएं को 8,440 फीट की गहराई तक ड्रिल किया गया। परीक्षण के दौरान यहां से हर दिन 13 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 327 बैरल कंडेनसेट (तेल जैसा तरल) का उत्पादन हासिल हुआ। यह उत्पादन अविनात वानिन और अविन काजा फॉर्मेशन से मिला है। मंत्रालय ने इस उपलब्धि को भारतीय ऊर्जा कंपनियों के बढ़ते वैश्विक विस्तार का मजबूत उदाहरण बताया है। साथ ही कहा गया कि यह खोज रणनीतिक अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के महत्व को भी दिखाती है। भारत लगातार विदेशों में ऊर्जा संपत्तियों में निवेश कर अपनी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है और यह सफलता उसी प्रयास का हिस्सा है। मंत्रालय ने इस अहम उपलब्धि पर कंसोर्टियम को बधाई देते हुए भविष्य में इन संसाधनों के समुचित दोहन की आशा व्यक्त की है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस जानकारी को अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर रिपोस्ट किया है।

भारतीय कंपनियों को मिला तेल-गैस भंडार, ईरान में जंग के बीच ऊर्जा सुरक्षा को नया सहारा

नईदिल्ली। भारत के ऊर्जा क्षेत्र के लिए एक बड़ी और राहत देने वाली खबर सामने आई है। लीबिया में भारतीय कंपनियों को तेल और गैस का नया भंडार मिला है, जिसे देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक अहम उपलब्धि माना जा रहा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पोस्ट में इस खोज की जानकारी दी है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी इस उपलब्धि को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कंसोर्टियम को बधाई दी है और भविष्य में इस संसाधन के बेहतर उपयोग की उम्मीद जताई है। यह खोज लीबिया के गदामेस बेसिन स्थित कॉन्ट्रैक्ट एरिया 95/96 में की गई है। इस परियोजना में ऑयल इंडिया लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारतीय कंसोर्टियम के हिस्से हैं, जबकि अल्जीरिया की कंपनी एसआईपीएक्स इस परियोजना की ऑपरेटर है। मंत्रालय ने इस खोज को भारतीय ऊर्जा कंपनियों के बढ़ते वैश्विक विस्तार का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया है। साथ ही कहा गया है कि यह सफलता अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की अहमियत को भी दर्शाती है। भारत लगातार विदेशों में ऊर्जा संपत्तियों में निवेश कर अपनी ऊर्जा जरूरतों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है, और यह खोज उसी रणनीति का हिस्सा है।

'बालिगों के बीच सहमति से लंबे समय तक बने शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं', हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप केस में एक आरोपी की अग्रिम याचिका पर मंगलवार (28 फरवरी) को सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि बालिगों के बीच सहमति से लंबे समय तक चलने वाला शारीरिक संबंध बलात्कार नहीं हो सकता है। कोर्ट ने इस केस में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर करते हुए यह आदेश दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस राजीव लोचन शुक्ला की सिंगल बेंच ने आरोपी को सशर्त अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि वो पुलिस जांच में सहयोग करेगा। इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं, जिसके बाद कोर्ट ने यह टिप्पणी की।

जानकारी के मुताबिक आरोपी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा तब खटखटाया जब मामले में कथित पीड़िता ने उसके खिलाफ BNS की अलग-अलग धाराओं के तहत FIR दर्ज कराई। आरोपी याचिकाकर्ता ने आजमगढ़ के सिधारी थाने में BNS की धारा 64, 115(2) और 351(3) के तहत FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करते हुए कोर्ट से अग्रिम जमानत देने की मांग की थी।

'रेप केस में फर्जी तरीके से फंसाया गया'

सुनवाई के दौरान याची के वकील ने कोर्ट ने दलील देते हुए कहा कि याची को बलात्कार केस में फर्जी तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने कोर्ट में अपनी सारी दलीलें रखीं। कोर्ट ने सभी तथ्यों के आधार पर माना कि सहमति से बालिगों के बीच लंबे समय से चले आ रहे फिजिकल रिलेशन को बलात्कार नहीं माना जा सकता है।

'सहमति से शारीरिक संबंध रेप नहीं'

सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि FIR में यह नहीं बताया गया कि पीड़िता और याचिकाकर्ता के बीच सहमति से रिश्ता था। BNSS 183 के तहत दर्ज बयान में पीड़िता का दावा है कि उसने साल 2022 से याची से फोन पर बात करना शुरू कर दिया था और उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए थे। वह लगभग 35 साल की विधवा है जिसका एक 15 साल का बेटा है। सभी तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने माना कि सहमति से बालिगों के बीच लंबे समय से चले आ रहे फिजिकल रिलेशन को रेप नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि जहां तक इस घटना का सवाल है जिसमें याची के बारे में कहा गया है कि उसने बंदूक की नोक पर पीड़िता के साथ रेप किया। कोर्ट की राय में यह BNSS की धारा 183के तहत दर्ज बयान में बताई गई कहानी से मेल नहीं खाती। कोर्ट ने माना कि BNSS की धारा 183 के तहत दर्ज बयान में याची और पीड़िता के प्रेम संबंध का पता चलता है। मेडिकल जांच के दौरान भी डॉक्टर को दिए गए बयान में पीड़िता और याचिकाकर्ता के 2024 से रिश्ते में होने की बात कही गई है।

बयान और FIR में अलग-अलग बात

पीड़ित जो एक विधवा है और उसका 15 साल का बेटा है उसने BNSS की धारा 173(4) के तहत एक अर्जी के आधार पर याची के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। BNS की धारा 183 के तहत दर्ज किया गया बयान FIR में बताई गई कहानी से बिल्कुल अलग है। धारा 183 के तहत दर्ज बयान में आपसी सहमति से संबंध दिखाया गया है और याचिकाकर्ता के खिलाफ BNS की धारा 64(1) के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। वहीं याची का कोई क्रिमिनल इतिहास नहीं है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि मामले में महिला ने दावा किया कि उसने 2022 से याचिकाकर्ता से बात करना शुरू किया था। हालांकि कोर्ट में सरकार की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका का विरोध किया गया। कहा गया कि याची इस मामले में अकेला नामजद आरोपी है। उसने पीड़िता का फायदा उठाते हुए बंदूक की नोक पर उसके साथ रेप किया।

अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर

याची की पत्नी ने भी पीड़िता को फ़ोन करके बताया कि याची के कई रिश्ते रहे है जिसके बाद उसने याची से संपर्क बंद कर दिया और उसके बाद अक्टूबर 2025 को याची ने पीड़िता के साथ रेप किया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि BNSS की धारा 173(4) के तहत एक आवेदन के आधार पर दर्ज की गई FIR में इन डिटेल्स का न होना कोर्ट की राय में प्रथम दृष्टया पूरी प्रॉसिक्यूशन कहानी पर शक पैदा करता है।

हिमंत सरमा का ममता पर तीखा हमला, 'आपका बयान खतरनाक–सांप्रदायिक है'

नई दिल्ली, एजेंसी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को विधानसभा चुनावों के दूसरे चरण की वोटिंग से पहले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर 'बांटने वाला और सांप्रदायिक' बयान देने का आरोप लगाया। एक एक्स पोस्ट में हिमंत बिस्वा सरमा ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उन्होंने एक खास समुदाय से डर होने का इशारा किया है। TMC पर हमला बोलते हुए, असम के मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल को 'तुष्टीकरण की प्रयोगशाला' कहा। सरमा ने लिखा कि बंगाल को बचाने की ज़रूरत है, अभी! ममता दीदी का यह बयान कि बंगाल के हिंदू एक खास समुदाय से सिर्फ इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि वह मुख्यमंत्री हैं, न सिर्फ परेशान करने

वाला है - बल्कि यह पूरी तरह से खतरनाक, बांटने वाला और सांप्रदायिक है। एक मौजूदा मुख्यमंत्री का यह दावा करना कि लोग सिर्फ उनकी वजह से 'सुरक्षित' हैं, और एक समुदाय से डर होने का इशारा करना, शासन की पूरी तरह से विफलता है और यह बंगाल की ज़मीनी हकीकत को दिखाता है कि कैसे आबादी में बदलाव ने उस ज़मीन को निगल लिया है जो कभी 'सोनार बांग्ला' थी।

बीजेपी की जीत का पूरा भरोसा जताते हुए उन्होंने आगे कहा कि दीदी का बयान बीजेपी की उस बात को और मज़बूत करता है जो वह शुरू से कहती आ रही है - कि TMC के राज में बंगाल को तुष्टीकरण, दंगों, सिंडिकेट, हिंसा, संदेशखाली जैसी ज़्यादतियों और आम लोगों में डर का एक 'प्रयोगशाला' बना दिया गया है।

पीएम मोदी का अलग अंदाज, गंगटोक में बच्चों के साथ खेला फुटबॉल

गंगटोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिक्किम दौरे पर हैं। मंगलवार की सुबह पीएम मोदी ने राजधानी गंगटोक में स्थानीय बच्चों के साथ फुटबॉल का आनंद लिया। पीएम ने बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, गंगटोक की एक प्यारी सुबह, सिक्किम में अपने नन्हे दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने का मजा ही कुछ और है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, इन युवाओं के साथ फुटबॉल का एक जबरदस्त सेशन। पीएम मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में कई तस्वीरें पोस्ट की हैं जिसमें वे स्थानीय बच्चों के साथ फुटबॉल खेलते, उनके साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान

पीएम पूरी तरह एक खिलाड़ी की वेशभूषा में हैं।

पीएम 27 अप्रैल की शाम को गंगटोक पहुंचे थे। उनका मंगलवार का कार्यक्रम काफी व्यस्त रहने वाला है। बच्चों के साथ समय बिताने के बाद प्रधानमंत्री गंगटोक स्थित ऑर्किडेरियम का दौरा करेंगे। वह पालजोर स्टेडियम में सिक्किम के राज्य स्थापना के 50वें वर्ष के समारोह के समापन समारोह में भाग लेंगे, जहां वे राज्य भर में 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे सभा को संबोधित भी करेंगे।

ये परियोजनाएं बुनियादी ढांचे, संपर्क, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बिजली, शहरी विकास, पर्यावरण, पर्यटन और कृषि सहित कई क्षेत्रों को कवर करती हैं, और इनका उद्देश्य सिक्किम में समग्र और समावेशी विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री युवा भागीदारी और खेल विकास को बढ़ावा देने के लिए पाकयोंग जिले के माइनिंग, रंगपो में इनडोर क्रिकेट सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी की यह यात्रा सिक्किम के राज्य बनने की स्वर्ण जयंती के वर्ष में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और राज्य तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के तीव्र और सतत विकास के प्रति वर्तमान सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।

रेलवे शताब्दी–जन शताब्दी ट्रेनों का बदलेगा लुक, अब यात्रियों को मिलेगी ये नई सुविधाएं

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय रेलवे सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने के साथ साथ अब अपनी पहले से चल रही प्रीमियम ट्रेनों को भी नए अंदाज में ढालने की योजना बना रहा है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। देशभर में चल रही करीब 100 शताब्दी और जनशताब्दी सेवाओं को बेहतर इंटीरियर, आधुनिक सुविधाओं और यात्रियों के अनुभव को सुधारने के लिए अपग्रेड किया जाएगा। हाल ही में रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में सभी जोनों को निर्देश जारी कर कहा कि, ट्रेनों के रेक की विस्तृत जांच करे। इनमें पाई जाने वाली कमियों को दूर करने के लिए तय समय में एक्शन प्लान तैयार करे। रेलवे के अनुसार, मुख्य फोकस इन ट्रेनों को आधुनिक बनाने और साफ-सफाई, भरोसेमंद सेवा व बेहतर सुविधाओं के जरिए यात्रियों की बढ़ती उम्मीदों को पूरा करना है। रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश में कहा कि, यात्रियों की सुविधा और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए इन ट्रेनों को अच्छी स्थिति में रखना बेहद जरूरी है। इस अपग्रेडेशन के तहत सबसे ज्यादा फोकस बाथरूम की साफ-सफाई और उनकी स्थिति सुधारने पर रहेगा। इसके अलावा सीटों को ज्यादा आरामदायक बनाने के लिए नई अपहोल्स्ट्री लगाई जाएगी और चार्जिंग पोर्ट व स्नैक्स टेबल जैसी सुविधाएं बेहतर की जाएंगी। साथ ही कोच में झटकों को कम कर सफर को ज्यादा स्मूथ बनाने पर भी काम होगा।

70 हजार के विवाद में हत्या, मां और तीन बेटों को फांसी की सजा, शेखर मर्डर केस में कोर्ट का बड़ा फैसला

आर्यावर्त क्रांति

मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर के भौराकलां थाना क्षेत्र के खेड़ी सूंडियान गांव में किसान शेखर की हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने आरोपी मां और उसके तीन बेटों को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह वारदात 17 जून 2019 को हुई थी।

मामले के अनुसार कस्बा सिसौली निवासी राजबाला देवी अपने बेटे शेखर के साथ खेड़ी सूंडियान गांव में 70 हजार रुपये उधार मांगने गई थीं। आरोप है कि इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। आरोपियों ने पहले पथराव किया और बाद में लाठी-

डंडों व ईंटों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल शेखर की मौके पर ही मौत हो गई थी।

घटना के बाद राजबाला देवी ने रामकुमार उर्फ रामू, उसकी पत्नी मुकेश उर्फ बिट्टो और उनके तीन बेटों प्रदीप, संदीप व सोनू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के दौरान रामकुमार उर्फ रामू की मौत हो जाने के कारण उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया। अदालत ने मां और तीन बेटों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि मृतक शेखर पर सात मुकदमे दर्ज थे और वह हिस्ट्रीशीटर था। साथ ही घटना के मोटिव और घटनास्थल को लेकर भी सवाल उठाए गए। हालांकि अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई और 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

रोज वैली केस में लाखों निवेशकों को राहत, ईडी ने लौटाए 127 .69 करोड़ रुपये

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोलकाता जोनल ऑफिस ने रोज वैली ग्रुप पोंजी स्कैम के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने की प्रक्रिया में एक अहम पड़ाव हासिल किया है। दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय ने एसेट डिस्पोजल कमेटी के साथ मिलकर इस काम को पूरा किया है।

जानकारी के अनुसार, अप्रैल 2026 तक इस मिली-जुली कोशिश ने फंड रिकवरी के कई चरणों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, और 1.7 लाख से ज्यादा निवेशकों को 127.69 करोड़ रुपये वापस दिलाने का काम किया है। इस रिकवरी प्रक्रिया को पारदर्शिता और पीड़ितों पर केंद्रित कानूनी कार्रवाई के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है।

इससे पता चलता है कि, ईडी की भूमिका सिर्फ जांच तक ही सीमित नहीं है। यह जब्त की गई संपत्तियों को बेचकर उनके असली मालिकों तक पहुंचाने में भी सक्रिय रूप से भूमिका निभा रहे है।

रोज वैली ग्रुप ने पश्चिम बंगाल, असम, ओडिशा और दूसरे राज्यों के निवेशकों से ऊंचे रिटर्न का वादा करके धोखाधड़ी से लगभग 17,520 करोड़ रुपये जुटाए थे, जिसमें से 6,666 करोड़ रुपये निवेशकों को वापस नहीं दिए गए थे।

जब से जांच शुरू हुई है, ईडी ने रोज वैली ग्रुप की संपत्तियों का पता लगाने, उन्हें अटैच करने, जब्त करने और सुरक्षित रखने के लिए पूरी ईमानदारी से कदम उठाए हैं।

सभी धर्म समान नहीं हैं सबरीमाला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वकील को क्यों लगाई फटकार?

नई दिल्ली, एजेंसी। केरलम के सबरीमाला मंदिर सहित अन्य संप्रदायों के धार्मिक स्थलों में महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मामले की सुनवाई से इतर दलीलें देने के लिए एक वकील को फटकार लगाई है। दरअसल, सबरीमाला मंदिर मामले पर 7 अप्रैल से सुनवाई शुरू हुई थी। इस दौरान केंद्र सरकार ने महिलाओं की एंट्री के विरोध में दलीलें रखीं। सरकार ने कहा था कि देश के कई देवी मंदिरों में पुरुषों की एंट्री भी बैन है, इसलिए धार्मिक परंपराओं का सम्मान किया जाना चाहिए।

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नौ जजों की बेंच ने एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय से कई बार कहा कि

वे अपनी दलीलें विचाराधीन मुद्दों तक ही सीमित रखें। अपनी दलीलों के दौरान, उपाध्याय ने तर्क दिया कि धर्म पंथ से श्रेष्ठ है, क्योंकि धर्म संघर्षों का स्रोत है। उन्होंने कहा कि पिछले 2000 वर्षों में सांप्रदायिक संघर्षों के कारण भारत 25 टुकड़ों में विभाजित हुआ और पिछले 200 वर्षों में भारत 7 देशों में विभाजित हुआ। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, इस बात पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि पीठ को अपने फैसले के परिणामों पर विचार करना होगा। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय से कई बार कहा, क्या अगले 25 वर्षों में हम चीन, सिंगापुर या जापान जैसे वैज्ञानिक रूप से एकीकृत देश बनेंगे, या पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश जैसे देश बन जाएंगे? उनके अनुसार, अनुच्छेद 25 और 26 अत्यंत प्रतिबंधात्मक तरीके से लिखे गए हैं और उन्होंने दावा किया कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का प्रचार करने का अधिकार कुछ पश्चिमी संविधानों में भी मान्यता प्राप्त नहीं है, जिनसे भारतीय संविधान ने कुछ पहलुओं को अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान उपाध्याय ने यह भी कहा कि संस्कृत में अंग्रेजी से अधिक अक्षर हैं और दावा किया कि डॉ। अंबेडकर ने इसे राजभाषा बनाने के लिए एक विधेयक पेश किया था। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में "संविधान" के लिए कोई उपयुक्त शब्द नहीं है। उनके अनुसार, इसका कारण अंग्रेजी भाषा की सीमा है, जिसमें केवल 26 अक्षर हैं जबकि संस्कृत में 52 अक्षर हैं।

केजरीवाल की राह पर मनीष सिसोदिया, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट के बहिष्कार का किया ऐलान

नई दिल्ली, एजेंसी। आम आदमी पार्टी (आप) के भीतर इन दिनों एक अलग ही तरह का 'सत्याग्रह' छिड़ गया है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद अब उनके सबसे करीबी माने जाने वाले मनीष सिसोदिया ने भी न्यायपालिका से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला कदम उठाया है। सिसोदिया ने दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अदालत का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने जज को एक पत्र लिखते हुए साफ कर दिया है कि अब से वह खुद या उनका कोई भी वकील इस अदालत की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए पेश नहीं होगा। मनीष सिसोदिया का यह आक्रामक कदम बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के उस फैसले की तरह है, जो उन्होंने ठीक एक दिन पहले लिया था। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी जस्टिस स्वर्ण कांता के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए

एक खुला खत लिखा था और उनके पूर्ण बहिष्कार की घोषणा करते हुए इस मुहिम को 'सत्याग्रह' का नाम दिया था। ठीक उसी तर्ज पर अब मनीष सिसोदिया ने भी जस्टिस शर्मा पर हितों के टकराव और पक्षपात करने की भारी आशंका जताते हुए खुद को इस अदालत की सुनवाई से पूरी तरह अलग कर लिया है। आप नेताओं के इस कदम ने कानूनी गलियारों में एक नई बहस छेड़ दी है। दरअसल, यह पूरा हाई-वोल्टेज ड्रामा दिल्ली के बहुचर्चित कथित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसने आम आदमी पार्टी की नींव हिला कर रख दी थी। इस हाई-प्रोफाइल और संवेदनशील मामले की सुनवाई फिलहाल जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में ही चल रही है। गौरतलब है कि इससे पहले निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए केजरीवाल और सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को इस मामले में आरोपमुक्त कर दिया था।

‘इस परिवार को आज के बाद…’, बेटे की शादी पर बजाया डी जे, पंचायत को नागवार गुजरी ये बात, सुनाया डाला ये फरमान

आर्यावर्त संवाददाता

ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के हाईटेक शहर कहे जाने वाले ग्रेटर नोएडा के नवादा गांव में एक परिवार को बेटे की शादी में डीजे बजाना भारी पड़ गया। गांव पंचायत के पुराने फैसले की अवहेलना करने पर पंचायत में परिवार के सामाजिक बहिष्कार का फैसला सुना दिया। इस फैसले के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया और मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक, करीब दो महीने पहले गांव में पंचायत बुलाई गई थी जिसमें सर्वसम्मति से शादी विवाह और अन्य आयोजनों में डीजे बजाने पर रोक लगाने का फैसला लिया गया था।

पंचायत का तर्क था कि डीजे से ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है सामाजिक

माहौल बिगड़ता है और कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। पंचायत में गांव के सभी परिवारों को फैसले का पालन करने के निर्देश दिए और चेतावनी भी दी गई कि जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सामाजिक कार्रवाई की जाएगी।

बताया जा रहा है कि हाल ही में गांव में एक परिवार ने बेटे की शादी की इस दौरान शादी में डीजे बजवाया। ग्रामीणों के अनुसार, यह पंचायत के फैसले का सीधा उल्लंघन माना गया। मामला सामने आते ही गांव के बुजुर्ग और पंचायत प्रतिनिधियों ने फिर से एक बैठक बुलाई। बैठक में इस घटना को पंचायत के आदेशों की अवहेलना माना गया और परिवार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया गया। पंचायत की बैठक में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से संबंधित परिवार के सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर दी। फैसले के तहत अब गांव का कोई भी व्यक्ति उसे परिवार को सामाजिक कार्यक्रमों में आमंत्रित नहीं करेगा। शादी भोज धार्मिक आयोजन और अन्य समुदाय कार्यक्रमों से परिवार को अलग रखने की बात कही गई। ग्रामीणों के मुताबिक, गांव में मुनादी कर इस फैसले की जानकारी भी दी गई ताकि पूरे गांव को पंचायत के आदेशों की जानकारी हो सके।

मुनादी से सुनाया गया फैसला गांव में बड़ी चर्चा

गांव में सार्वजनिक रूप से मुनादी कर फैसले का ऐलान किए जाने के बाद यह मामला और तूल पकड़ गया है। सामाजिक बहिष्कार जैसे कठोर कदम को लेकर गांव में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ लोग इस पंचायत के अनुशासन और सामूहिक निर्णय की मजबूती बता रहे हैं। जबकि, कुछ इस बेहद सख्त कदम मान रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार, पंचायत का मानना है कि डीजे के कारण संस्कृति और गांव में पारंपरिक मर्यादाएं प्रभावित हो रही हैं।

कई बार तेज आवाज देर रात शोर और गानों को लेकर विवाद भी पैदा होते रहते हैं। इसी वजह से पंचायत ने पहले ही डीजे पर रोक लगाकर सामूहिक सहमति बनाई थी। लेकिन इस फैसले के उल्लंघन ने पूरे विवाद को जन्म दे दिया। हालांकि, पंचायत के फैसले ने सामाजिक बहिष्कार जैसे कदम को लेकर बहस भी छेड़ दी है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसी भी शादी में डीजे बजाने पर इतना बड़ा दंड उचित है। कई लोग मानते हैं कि पंचायत के नियमों का पालन जरूरी है। लेकिन सामाजिक बहिष्कार जैसा फैसला बेहद कठोर माना जा सकता है।

गांव की परंपरा बनाम व्यक्तिगत स्वतंत्रता

यह मामला सिर्फ डीजे बजाने का नहीं। बल्कि गांव की सामूहिक परंपरा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के टकराव के रूप में भी देखा जा रहा है। एक ओर पंचायत सामुदायिक अनुशासन की बात कर रही है तो दूसरी ओर व्यक्तिगत अधिकारों को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। मामले के तूल पकड़ने के बाद संभावना जताई जारी है कि यह मुद्दा प्रशासन तक भी पहुंच सकता है। सामाजिक बहिष्कार जैसे फैसलों को लेकर कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर भी चर्चा हो सकती है।

डीपीआरओ पर शासनादेश क़े उल्लंघन क़े आरोप

सुल्तानपुर। जिले में तैनात जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ला एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। उन पर शासनादेश की खुलेआम अनदेखी करने के आरोप लग रहे हैं।

बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने करीबी और पसंदीदा ग्राम पंचायत व ग्राम विकास अधिकारियों को नियमों के विरुद्ध एक से अधिक क्लस्टर आवंटित कर दिए हैं। जबकि शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि ग्राम विकास अधिकारियों और ग्राम पंचायत अधिकारियों के बीच क्लस्टर का समान वितरण किया जाए।

मामला केवल एक ब्लॉक तक सीमित नहीं है। भदैया ब्लॉक के कई पीड़ित अधिकारियों ने महीनों पहले ही जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी से इसकी शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। आरोप है कि जिले के लगभग सभी ब्लॉकों में इसी तरह से करीबी अधिकारियों को कई-कई क्लस्टर दिए गए हैं।

कभीएडीएमतोकभीएसडीएम…बरेलीकी विप्राऔरशिखाखुदकोबतातींआईएएस, इन 2ठगबहनोंनेकैसेकियाफर्जीवाड़ा?

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

बरेली। उत्तर प्रदेश के बरेली में ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां दो बहनों ने खुद को आईएएस अधिकारी बताकर कई लोगों से लाखों रुपये ठग लिए। दोनों बहनें अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देती थीं। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए दोनों बहनों समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

पूरा मामला बारादरी थाना क्षेत्र का है, जहां चार पीड़ितों ने मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की और पूरे गिरोह का खुलासा हो गया।

नौकरी का लालच देकर ऐंठे लाखों रुपये

पुलिस के अनुसार, आरोपी बहनों के नाम विप्रा और शिखा हैं। ये दोनों कभी खुद को प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी बताती थीं, तो कभी एडीएम या एसडीएम बनकर लोगों को प्रभावित करती थीं। इनके बोलने का तरीका और आत्मविश्वास ऐसा था कि लोग आसानी से इनके झांसे में आ जाते थे। ये बहनें खासतौर पर बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाती थीं। उनसे कहती थीं कि उनकी सरकारी नौकरी पक्की लगवा देंगी। इसके बदले में वे मोटी रकम मांगती थीं। कई युवाओं ने नौकरी की उम्मीद में अपनी जमा पूंजी तक इन्हें दे दी।

फाइक एन्क्लेव की रहने वाली प्रीति लॉयल समेत चार लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। इन लोगों ने आरोप लगाया कि उनसे करीब साढ़े 11 लाख रुपये ठगे गए हैं। जब काफी समय तक नौकरी नहीं लगी और बहनों ने बहाने बनाना शुरू किया, तब उन्हें ठगी का अहसास हुआ।

क्या बोले पुलिस अधिकारी?

बारादरी थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तेजी से जांच की। इसके बाद दोनों बहनों और उनके एक साथी को गिफ्तार कर लिया है। पूछताछ में कई अहम बातें सामने आई हैं। पुलिस को शक है कि इस ठगी के रैकेट में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। ये लोग मिलकर लंबे समय से इस तरह की धोखाधड़ी कर रहे थे। अभी पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और बाकी साथियों की तलाश भी जारी है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार को सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगर जांच में और पीड़ित सामने आते हैं, तो उनके बयान लेकर मामले में और धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं।

लोगों से सतर्क रहने की अपील

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि कोई भी व्यक्ति अगर खुद को बड़ा अधिकारी बताकर नौकरी या किसी काम के नाम पर पैसे मांगे, तो तुरंत सतर्क हो जाएं। बिना जांच-पड़ताल के किसी को भी पैसा न दें। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही इस गिरोह के बाकी सदस्यों को भी पकड़ लिया जाएगा।

ईकार्ट डिलीवरी पार्टनर्स ने किया प्रदर्शन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। भुगतान में कटौती बढ़ाने व न्यूनतम मजदूरी न देने से नाराज डिलेवरी पार्टनर्स ने मंगलवार को ईकार्ट कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। विरोध करने वालों ने न्यूनतम मजदूरी भुगतान कराने की मांग की है।

विरोधकर्ताओं करने वालों का कहना है को दिन-रात मेहनत करने वाले डिलीवरी पार्टनर्स की स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। EKart Logistic जैसी बड़ी कंपनी में पहले प्रति पार्सल लगभग ₹18 तक भुगतान मिलता था, लेकिन अब कई जगह यह घटाकर ₹12 से ₹10 तक कर दिया गया है। इससे डिलीवरी कर्मचारियों में नाराज़गी और असंतोष बढ़ रहा है।

डिलीवरी पार्टनर्स का कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। पेट्रोल, मोबाइल रिचार्ज, बाइक सर्विस, टायर, इंश्योरेंस और रोजमर्रा के खर्च पहले से कहीं ज्यादा हो चुके हैं। ऐसे समय में मेहनताना बढ़ाने के बजाय कम कर देना कर्मचारियों के साथ अन्याय जैसा महसूस होता है।

एक डिलीवरी पार्टनर ने बताया कि रोज 10 से 12 घंटे मेहनत करने के बाद भी पहले जैसी कमाई नहीं हो पा रही है। अगर किसी दिन पार्सल कम मिले या दूरी ज्यादा हो, तो कमाई और भी घट जाती है। इससे परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है। सरकार और श्रम विभाग से मांग की गई है की गिग वर्कर्स और डिलीवरी कर्मचारियों को न्यूनतम उचित भुगतान सुनिश्चित किया जा सके। इसमें सूरज अग्रहरि दीपक मौर्य सत्यप्रकाश पांडे राम औतार राय विकम गुप्ता वीरेंद्र यादव सहित दर्जनों डिलीवरी पार्टनर उपस्थित रहे व कम्पनी कर्मचारियों को मांग पत्र सौंपा।

1 मिनट में 10 बार शट अप बोलने वाली प्रिंसिपल पर एफआईआर, स्कूल पर भी लगेगा ताला

आर्यावर्त संवाददाता

हरदोई। पिछले तीन दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने हरदोई से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा दिया है। हरदोई के सनबीम इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रिंसिपल ममता मिश्रा द्वारा एक महिला अभिभावक की सरेआम बेइज्जती करने के मामले में अब प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। मामले में FIR दर्ज की गई है। साथ ही स्कूल की मान्यता रद्द करने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीड़ित महिला के आंसुओं ने पूरे सिस्टम को झकझोर दिया, जिसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग और पुलिस, दोनों ही फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। पीड़ित महिला अभिभावक नीलम वर्मा ने बताया कि उन्होंने अपनी बेटी अलीशा के लिए स्कूल के निर्देशानुसार बाहर से कोर्स खरीद लिया था। इसके बावजूद स्कूल प्रबंधन ने 1200 रुपये की अतिरिक्त चार कॉपियां स्कूल से ही खरीदने का

दबाव बनाया। नीलम जब प्रिंसिपल ममता मिश्रा से 10 दिन की मोहलत मांगने गईं, तो प्रिंसिपल ने आपा खो दिया।

48 घंटे के भीतर एफआईआर और SC-ST एक्ट में मुकदमा

वीडियो वायरल होने के बाद जब मामला तूल पकड़ने लगा, तो प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने भी इस पर संज्ञान लिया। इसके 48 घंटे के भीतर हरदोई शहर कोतवाली में प्रिंसिपल ममता मिश्रा के विरुद्ध SC-ST एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसपी अशोक कुमार मीणा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला पंजीकृत कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई प्रचलित है।

प्रिंसिपल के स्कूल जाने पर रोक, मान्यता पर लटकी तलवार

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) अजीत सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया। जांच में प्रिंसिपल का आचरण और विद्यालय की कार्यप्रणाली मानकों के विपरीत पाई गई। बीएसए के आदेशानुसार प्रिंसिपल ममता मिश्रा के विद्यालय परिसर में प्रवेश पर तत्काल रोक लगा दी गई है। स्कूल द्वारा कॉपियों के लिए बनाए जा रहे अवैध दबाव और अभद्र व्यवहार के कारण विद्यालय की मान्यता रद्द करने की कवायद शुरू कर दी गई है। BSA अजीत सिंह ने स्पष्ट किया कि अभिभावकों के साथ इस तरह का व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह मामला अन्य निजी स्कूलों के लिए भी एक बड़ी नजीर बनेगा।

वैशाली से गोकुलपुरी… हिंडन एयरपोर्ट भी जाना होगा आसान, 16 KM लंबे मेट्रो कॉरिडोर में खास क्या?

आर्यावर्त संवाददाता

गाजियाबाद। गाजियाबाद में मेट्रो कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) से ब्लू लाइन के वैशाली टर्मिनल स्टेशन को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के गोकुलपुरी से जोड़ने वाली नई मेट्रो लाइन के लिए डीपीआर तैयार करने का अनुरोध किया है। यह प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर करीब 16 किलोमीटर लंबा होगा।

इस नई मेट्रो लाइन की खास बात यह है कि यह हिंडन सिविल टर्मिनल से होकर गुजरेगी, जो फिलहाल दिल्ली-एनसीआर के दूसरे हवाई अड्डे के रूप में काम कर रहा है। प्रस्तावित रूट पर लगभग सात स्टेशन बनाए जाने की संभावना है। यह कॉरिडोर साहिबाबाद, मोहन नगर, पसुंडा, हिंडन सिविल टर्मिनल और गगन विहार जैसे प्रमुख इलाकों को जोड़ेगा, जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। दरअसल, डीएमआरसी ने पिछले साल जुलाई में मेट्रो विस्तार योजना के पांचवें चरण के तहत दिल्ली-एनसीआर में 18 नई परियोजनाओं का प्रस्ताव रखा था, जिनमें से तीन गाजियाबाद से जुड़ी थीं। इसी योजना को आगे बढ़ाते हुए जीडीए ने वैशाली-गोकुलपुरी कॉरिडोर के लिए डीपीआर तैयार करने को कहा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि आने वाले कुछ महीनों में यह रिपोर्ट तैयार होकर जमा हो जाएगी।

पहले डीएमआरसी की योजना के तहत गोकुलपुरी को हिंडन सिविल टर्मिनल के रास्ते रेड लाइन के अर्थला स्टेशन से जोड़ने के लिए 12-13 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर प्रस्तावित था। लेकिन अब जीडीए इस योजना का विस्तार करना चाहता है, ताकि इंदिरापुरम, वसुंधरा और वैशाली जैसे घनी आबादी वाले इलाकों के करीब पांच लाख से ज्यादा लोगों को बेहतर परिवहन सुविधा मिल सके। वर्तमान में हिंडन सिविल टर्मिनल की स्थिति यह है कि यह नजदीकी मेट्रो स्टेशनों दिलशाद गार्डन और मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर से लगभग पांच किलोमीटर दूर है। ये दोनों स्टेशन रेड लाइन पर स्थित हैं, जिससे यात्रियों को अंतिम दूरी तय करने में दिक्कत होती है। हालांकि साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन एक तेज विकल्प देता है, लेकिन यहां भी अंतिम मील की कनेक्टिविटी के लिए लोगों को ऑटो और कैब पर निर्भर रहना पड़ता है।

इसके अलावा, शहर में दो अन्य मेट्रो परियोजनाएं भी प्रस्तावित हैं। इनमें रेड लाइन पर शहीद स्थल न्यू बस अड्डा से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन तक तीन किलोमीटर का विस्तार और नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी से साहिबाबाद तक पांच किलोमीटर लंबा लिंक शामिल है। यह लिंक इंदिरापुरम, शक्ति खंड और वसुंधरा सेक्टर-5 को जोड़ेगा और इसमें पांच स्टेशन बनाए जाएंगे।

7,500 करोड़ रुपये होंगे खर्च

इन तीनों कॉरिडोर के पूरा होने पर गाजियाबाद में मेट्रो नेटवर्क करीब 25 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा। इस पूरी परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 7,500 करोड़ रुपये बताई जा रही है, जो औसतन 300 करोड़ रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से है। हालांकि, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी-साहिबाबाद कॉरिडोर 2018 से फंड की कमी के कारण अटका हुआ है, जबकि इसकी डीपीआर पहले ही तैयार की जा चुकी है। अब आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा डीपीआर तैयार करने के निर्देश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि केंद्र और राज्य सरकार से वित्तीय सहायता मिल सकेगी। अधिकारियों का कहना है कि फंडिंग पहले एक बड़ी बाधा थी, लेकिन अब परियोजनाओं के जल्द शुरू होने की संभावना बढ़ गई है।

22 महीने तक रहे ‘ सबके खास’, सख्ती बढ़ी तो अचानक गाली बाज बने ट्रैफिक इंस्पेक्टर

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव की कोशिशें अब विभाग के भीतर ही खींचतान का कारण बनती दिख रही हैं। करीब 22 महीने से ट्रैफिक इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे निरीक्षक राम निरंजन यादव, जो कभी अपने सहयोगियों के बीच एक सक्षम नेतृत्वकर्ता के रूप में जाने जाते थे, अब अचानक विवादों के केंद्र में आ गए हैं। बताया जा रहा है कि हाल ही में पुलिस कप्तान द्वारा शहर के भीतर यातायात सुधार के लिए नया डायवर्जन और रोड मैप लागू किया गया है। इस नई व्यवस्था ने जहां ट्रैफिक को सुचारू करने की कोशिश की है, वहीं ड्यूटी में लगे पीआरडी और होमगार्ड जवानों की जिम्मेदारियां भी बढ़ा दी हैं। बढ़ते कार्यभार और सख्त निगरानी के चलते कुछ कर्मियों में असंतोष पनपने लगा है।

सूत्रों की मानें तो इसी असंतोष के बीच ट्रैफिक इंस्पेक्टर पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल के आरोप लगाए गए हैं। जिन जवानों के साथ कभी उनका तालमेल बेहतर माना जाता था, वही अब उनके खिलाफ शिकायत लेकर सामने आए हैं। इस पूरे मामले की जांच सीओ सिटी सौरभ सामंत को सौंपी गई है। हालांकि, विभागीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि सख्ती और अनुशासन लागू करने की कोशिशें अक्सर विरोध को जन्म देती हैं। कप्तान की नई कार्यशैली का असर सिविल और ट्रैफिक पुलिस दोनों में साफ नजर आ रहा है, जहां कामकाज की गति तो बढ़ी है, लेकिन उसके साथ तनाव भी उभरकर सामने आ रहा है। शायद यही वजह है कि ख़ासकर ट्रैफिक ड्यूटी में लगे आराम तलब कर्मियों को कप्तान मैडम का यह फरमान भारी पड़ रहा है।

राजस्थान के रेगिस्तान से भी गर्म उत्तर प्रदेश का ये शहर, 72 घंटे बाद पलटेगा मौसम

आर्यावर्त संवाददाता

बांदा। अप्रैल के महीने में जब भीषण गर्मी की बात होती है, तो सबसे पहले राजस्थान के मरुस्थलीय जिले जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, चुरू और गंगानगर का नाम सामने आता है। यहां हर साल तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचना आम बात है। लेकिन इस साल मौसम ने अजीब करवट बदली है। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला इस बार गर्मी के मामले में राजस्थान के इन जिलों को पीछे छोड़ दिया है।

सोमवार को बांदा में अधिकतम तापमान 47.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का ही नहीं, बल्कि अप्रैल का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। इससे पहले यहां 30 अप्रैल 2022 और 25 अप्रैल 2026 को 47।4 डिग्री

सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। राजस्थान के जैसलमेर में अधिकतम तापमान सोमवार को 46.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो बांदा से कम रहा। इससे पहले जैसलमेर में 18 अप्रैल 2025 को 46.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। बांदा के अलावा झांसी भी भीषण गर्मी से जूझ रहा है, जहां तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने बताया कि बुंदेलखंड के कई जिलों जैसे बांदा, झांसी और उरई में लू का प्रकोप बना हुआ है।

राजधानी लखनऊ में भी गर्मी का असर साफ दिखाई दिया। यहां सोमवार को अधिकतम तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.8 डिग्री अधिक है, जबकि न्यूनतम तापमान 24.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.7 डिग्री ज्यादा है। इसके अलावा आगरा में 44.4 डिग्री और प्रयागराज, हमीरपुर व उरई में 44.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

72 घंटों के भीतर बारिश का अलर्ट

हालांकि इस भीषण गर्मी के बीच राहत की खबर भी सामने आई है। मौसम विभाग ने बांदा और आसपास के इलाकों में अगले 72 घंटों के भीतर बारिश की संभावना जताई है। अनुमान है कि 29 अप्रैल को अधिकतम तापमान घटकर 44 डिग्री सेल्सियस तक आ सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास रहेगा। 1 मई तक तापमान में मामूली गिरावट बनी रहने की संभावना है। बारिश और तेज हवाओं के कारण तापमान में 1 से 2 डिग्री की कमी आ सकती है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। बढ़ती गर्मी और लू के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने भी एहतियाती कदम उठाए हैं। सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूलों में पर्याप्त पानी की व्यवस्था और लू से बचाव के उपाय लागू किए जा रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को ओआरएस, ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स और प्राथमिक उपचार सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान के बाड़मेर में सोमवार को तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि कोटा और वनस्थली में 45.7 डिग्री, फलोदी और चित्तौड़गढ़ में 45।4 डिग्री, चुरू में 45.3 डिग्री और पिलानी व बीकानेर में 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

हमीरपुर में भीषण सड़क हादसा, बरातियों से भरी गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर, दूल्हे के भाई समेत 4 की मौत

आर्यावर्त संवाददाता

हमीरपुर। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। बरातियों से भरी ईको वैन को एक तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दूल्हे के भाई समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि ट्रक चालक वैन को लगभग 100 मीटर तक घसीटता ले गया।

यह घटना मौदहा कोतवाली क्षेत्र के छिरका गांव के पास NH-34 पर हुई। बताया जा रहा है कि सभी लोग एक ईको वैन में सवार होकर महोबा जिले में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी छिरका गांव के पास पहुंची, तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक डंपर ने नियंत्रण खो दिया और वैन में टक्कर मार दी। टक्कर की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल

की ओर दौड़ पड़े।

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया और वैन में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन घायलों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फरार ट्रक चालक का पीछा किया और उसे घटनास्थल से करीब 10 किलोमीटर दूर ट्रक समेत पकड़ लिया। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक मृगांक पाठक ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

परिवारों में मचा कोहराम

मृतकों की पहचान वैन चालक कमलेश (45) निवासी डामर गांव, जीतू (30), दूल्हे रमाकांत के छोटे भाई शशिकांत (30) और मोहन (24) के रूप में हुई है। वहीं घायलों में रोहित (19), दिलीप (60) और कमलेश (30) शामिल हैं। सभी मृतक और घायल कुरारा थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। इस हादसे के बाद परिवारों में कोहराम मच गया है। जो लोग खुशी के मौके पर शामिल होने जा रहे थे, उन्हें क्या पता था कि रास्ते में ऐसा भीषण हादसा उनका इंतजार कर रहा है।

'936 प्रधान परिचालकों की भर्ती से दूरसंचार व्यवस्था होगी और सशक्त'

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संचार किसी भी व्यवस्था का एक सशक्त माध्यम होता है। संचार व्यवस्था जितनी मजबूत होगी, पुलिस या अन्य बल उतने ही प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेंगे, सटीक कार्रवाई कर पाएंगे तथा आमजन को समय पर राहत उपलब्ध करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग में 936 नए प्रधान परिचालकों के चयन से संचार इकाई को और अधिक सशक्त बनाने में सहायता मिलेगी।मुख्यमंत्री लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रक्रिया के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग के नवचयनित 936 प्रधान परिचालक तथा प्रधान परिचालक (यांत्रिक) को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से 10 नवचयनित

अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम से पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग की उपलब्धियों पर आधारित एक लघु चलचित्र भी प्रदर्शित किया गया।मुख्यमंत्री ने कहा कि नवचयनित 936 प्रधान परिचालकों की भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शी तथा आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए अभ्यर्थियों की योग्यता और क्षमता के आधार पर संपन्न कराई गई है। इन सभी कर्मियों को आठ माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें उन्हें सामान्य वॉकी-टॉकी प्रणाली से लेकर दूरसंचार की आधुनिक तकनीकों तक का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पुलिस कार्मिक के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तभी वे देश और समाज की ईमानदारीपूर्वक सेवा कर सकेंगे।मुख्यमंत्री ने कहा कि नवचयनित कर्मियों को देश ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सिविल पुलिस का हिस्सा बनने का अवसर मिला है। उन्होंने बताया कि हाल ही में प्रदेश के 112 केंद्रों पर 60,244 पुलिस आरक्षियों की दीक्षांत परेड आयोजित की गई। विगत नौ वर्षों में प्रदेश में दो लाख 20 हजार से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती सफलतापूर्वक संपन्न की जा चुकी है।उन्होंने कहा कि नौ वर्ष पहले निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया संपन्न कराना कठिन था, लेकिन वर्तमान व्यवस्था में यदि किसी व्यक्ति में क्षमता है तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। प्रदेश सरकार ने अभ्यर्थियों और उनके परिवारों की अपेक्षाओं के अनुरूप भर्ती प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया है। इसलिए अब नवचयनित कर्मियों का दायित्व है कि वे भी उसी नीयत और ईमानदारी के साथ राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में केवल तीन हजार पुलिस कार्मिकों को एक साथ प्रशिक्षण देने की क्षमता थी, जबकि वर्ष 2025 में 60,244 पुलिस कार्मिकों को प्रदेश के प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट नीति, साफ नीयत और दृढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम है। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में तीन दिनों के भीतर 40 हजार से अधिक होमगार्ड कार्मिकों की भर्ती परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गईं और इस वर्ष लगभग एक लाख नई भर्तियां की जाएंगी, जिनमें होमगार्ड, सिविल पुलिस और उप निरीक्षक के पद शामिल हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जहां 500 से अधिक कुशल खिलाड़ियों को पुलिस बल में शामिल किया गया है। इसी का परिणाम है कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश पुलिस बड़ी संख्या में पदक प्राप्त कर रही है।उन्होंने कहा कि प्रदेश में पुलिस की अवस्थापना सुविधाओं में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। वर्ष 2017 में प्रदेश के 10 जनपदों में पुलिस लाइन नहीं थी और कई थानों के पास स्वयं का भवन नहीं था, जबकि आज 55 जनपदों में आधुनिक बहुमंजिला भवनों में बैरक की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मॉडल थानों का निर्माण तथा नए अग्निशमन केंद्रों की स्थापना की जा रही है। इसके साथ ही विशेष सुरक्षा बल, राज्य आपदा मोचन बल तथा महिला सशस्त्र आरक्षित बल की तीन नई बटालियनों का गठन किया गया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में राज्य स्तरीय विधि विज्ञान संस्थान सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है तथा 12 उच्च श्रेणी की विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं संचालित हैं और छह नई प्रयोगशालाएं निर्माणाधीन हैं। नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद प्रत्येक जनपद में दो-दो चलित विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं, जिनमें प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात किया गया है।उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ होने से निवेश का वातावरण बेहतर हुआ है और प्रदेश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। कानून का राज विकास की पहली गारंटी होता है और इसी के परिणामस्वरूप देश और दुनिया के बड़े निवेशक प्रदेश में निवेश के लिए आगे आ रहे हैं।कार्यक्रम को वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना तथा उत्तर प्रदेश पुलिस दूरसंचार विभाग के महानिदेशक आशुतोष पाण्डेय ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना संजय प्रसाद, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के महानिदेशक एस.बी. शिराडकर, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय डॉ. संजीव गुप्ता सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

को-ऑपरेटिव संघ चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की ऐतिहासिक जीत, सभी पदों पर निर्विरोध चयन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव संघ के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी समर्थित उम्मीदवारों ने ऐतिहासिक विजय हासिल करते हुए सभापति, उपसभापति सहित सभी संचालक पदों पर निर्विरोध जीत दर्ज की है। इस उपलब्धि पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी तथा प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने नव निर्वाचित सभापति चौधरी शिवेन्द्र सिंह तथा उपसभापति ब्रज किशोर गुप्ता सहित सभी संचालकों को शुभकामनाएं देते हुए विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव संघ विकास, पारदर्शिता और जनसेवा के नए आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने निर्विरोध निर्वाचित संचालकों रामनिवास यादव, बालेन्द्र प्रताप सिंह, शारदा चौधरी, आकांक्षा सोनकर तथा ऊर्षा मौर्या को भी विजय की बधाई दी।

○ संक्षेप ○

गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के तहत दबंग व्यक्ति छह माह के लिए जिलाबदर

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ के अंतर्गत थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के एक मनबढ़ एवं दबंग व्यक्ति को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम-1970 के तहत छह माह के लिए लखनऊ की सीमा से निष्कासित (जिलाबदर) करने का आदेश पारित किया गया है।पुलिस आयुक्त न्यायालय, लखनऊ में लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से वाद संख्या 62(13)/2026 की सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान विपक्षी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को सुना गया। राज्य की ओर से उपस्थित संयुक्त निदेशक अभियोजन अवधेश कुमार सिंह ने अपने तर्कों के माध्यम से विपक्षी को लखनऊ की सीमा से निष्कासित किया जाना उचित बताया।न्यायालय ने संयुक्त निदेशक अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद 27 अप्रैल 2026 को खुले न्यायालय में आदेश पारित किया। आदेश के तहत विपक्षी को गुण्डा घोषित करते हुए उसके आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से उसे लखनऊ की सीमा से छह माह के लिए निष्कासित (जिलाबदर) कर दिया गया।पुलिस के अनुसार जिलाबदर किया गया व्यक्ति परवेज उर्फ मुन्ना (36 वर्ष) पुत्र पुत्तन खान, निवासी डूडा कॉलोनी राधाग्राम थाना ठाकुरगंज क्षेत्र का रहने वाला है। उसके विरुद्ध पूर्व में थाना वजीरगंज एवं थाना ठाकुरगंज में मारपीट एवं अन्य गंभीर धाराओं में एक से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार की कार्यवाही का उद्देश्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है।

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के वीडियो प्रकरण पर अखिलेश यादव का हमला, सख्त कार्रवाई की उठाई मांग

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बंगाल चुनाव के दौरान पर्यवेक्षक बनाए गए उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से जुड़े कथित अभद्र वीडियो प्रकरण को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस वीडियो के सार्वजनिक होने से उत्तर प्रदेश सरकार के शासन-प्रशासन की छवि को गंभीर क्षति पहुंची है और सरकार द्वारा किए जा रहे महिला सम्मान और नारी सुरक्षा के दावों की वास्तविकता भी सामने आ गई है।अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा शासन-प्रशासन में इस प्रकार के व्यक्ति और अधिकारी अपवाद नहीं रह गए हैं, जिससे महिलाओं के मन में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जब महिला सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले ही इस प्रकार के आचरण में लिप्त पाए जाते हैं, तो आम महिलाओं के मन में अपनी सुरक्षा को लेकर स्वाभाविक रूप से चिंता उत्पन्न होती है।उन्होंने कहा कि इस घटना से भाजपा से जुड़ी महिलाओं में भी असहजता और शर्मिंदगी की स्थिति बनी है, क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा हर परिवार से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित अधिकारी के विरुद्ध निलंबन या बर्खास्तगी जैसी कार्रवाई कितनी शीघ्र की जाती है।अखिलेश यादव ने कहा कि इस प्रकरण का सीधा संबंध मुख्यमंत्री की छवि से भी जुड़ा हुआ है और इस मामले में की जाने वाली कार्रवाई से यह स्पष्ट होगा कि सरकार और मुख्यमंत्री का इस मुद्दे पर क्या रुख है। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर प्रकरण के सामने आने के बाद सरकार को अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को इस प्रकार के मामलों में किसी भी प्रकार का बहाना बनाने के बजाय स्पष्ट और कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अपराध के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति केवल अपराधियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि ऐसे अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू होनी चाहिए, ताकि कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था में जनता का विश्वास बना रहे।

शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और धमकी देने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

लखनऊ। थाना विकासनगर पुलिस ने शादी का झांसा देकर महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने तथा अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार 23 मार्च 2026 को वादिनी द्वारा थाना विकासनगर में लिखित सूचना दी गई थी कि विपक्षी अनुग्रह नरायण पुत्र आदित्य नरायण झा ने उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए तथा उसके अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी दी। साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। इस शिकायत के आधार पर थाना विकासनगर में मुकदमा संख्या 53/2026 धारा 69, 351(3), 352 तथा 316(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।मामले की विवेचना के दौरान अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसी क्रम में 28 अप्रैल 2026 को विकासनगर पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त अनुग्रह नरायण को 17/30 इंदिरानगर थाना गाजीपुर क्षेत्र के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त ने महिला को शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और बाद में अश्लील फोटो तथा वीडियो बनाकर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर दबाव बनाने का प्रयास किया। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए रिमांड की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है।पुलिस के अनुसार अभियुक्त अनुग्रह नरायण पुत्र आदित्य नरायण झा, निवासी 17/30 इंदिरानगर थाना गाजीपुर, लखनऊ के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमे में अन्य आवश्यक साक्ष्य संकलन और वैधानिक कार्रवाई जारी है।इस गिरफ्तारी अभियान को सफल बनाने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक भानु प्रताप सिंह, आरक्षी राघवेन्द्र सिंह तथा महिला आरक्षी रीना सरोज शामिल रहीं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है तथा आगे की कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है।

नगर निगम की बड़ी कार्रवाई, हसनपुर खेवली में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाकर लगभग चार करोड़ की संपत्ति कराई कब्जामुक्त

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। नगर निगम लखनऊ द्वारा सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए ग्राम हसनपुर खेवली क्षेत्र में अवैध कब्जे के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। यह कार्रवाई नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देशन तथा अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में की गई, जिसमें प्रशासनिक टीम ने मौके पर पहुंचकर प्रभावी ढंग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया।अभियान के दौरान ग्राम हसनपुर खेवली (अंसल), तहसील सरोजनी नगर, जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 710 की सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराया गया। इस गाटा का कुल क्षेत्रफल 0.607 हेक्टेयर ऊसर भूमि है, जिसमें से 0.253 हेक्टेयर भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास

किया जा रहा था। स्थानीय स्तर पर अस्थायी बाउंड्री वॉल बनाकर तथा पौधरोपण कर भूमि पर स्वामित्व स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी।नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का निरीक्षण किया और जेसीबी मशीन की सहायता से अवैध रूप से बनाई गई बाउंड्री वॉल तथा अन्य अस्थायी निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए सरकारी भूमि को सुरक्षित कराया। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई योजनाबद्ध तरीके से की गई, जिससे किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो और सरकारी संपत्ति को नुकसान से बचाया जा सके।इस अभियान का नेतृत्व सहायक नगर आयुक्त एवं प्रभारी अधिकारी (संपत्ति) रामेश्वर प्रसाद तथा तहसीलदार नगर निगम अरविंद पाण्डेय द्वारा गठित टीम ने किया। मौके पर नायब तहसीलदार तेजस्वी प्रकाश के नेतृत्व में पूरी टीम सक्रिय रही और कार्रवाई को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया। इस दौरान राजस्व निरीक्षक प्रदीप गिरी, नगर निगम लेखपाल अनुपम कुमार, संदीप कुमार तथा राजस्व लेखपाल ओम प्रकाश गौड़ सहित नगर निगम की प्रवर्तन टीम भी मौके पर मौजूद रही और अभियान को सुचारु रूप से संचालित किया।नगर निगम अधिकारियों के अनुसार कब्जामुक्त कराई गई 0.253 हेक्टेयर भूमि की वर्तमान बाजार कीमत लगभग चार करोड़ रुपये आंकी गई है। इस कार्रवाई को सरकारी संपत्ति की सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम द्वारा सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने का अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। जहां भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की सूचना प्राप्त होगी, वहां त्वरित कार्रवाई करते हुए भूमि को मुक्त कराया जाएगा, ताकि सरकारी संपत्तियों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और भविष्य में अतिक्रमण की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

पारिवारिक विवाद के चलते राजमिस्त्री ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस जांच में जुटी

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। थाना मोहनलालगंज क्षेत्र के ग्राम कल्ली पूरब घाघ में मंगलवार सुबह एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू करते हुए शव को कब्जे में लेकर आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी।पुलिस के अनुसार 28 अप्रैल 2026 को प्रातः लगभग 7 बजे थाना मोहनलालगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कल्ली पूरब घाघ में एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया।मौके पर जांच के दौरान पता चला कि बब्लू गौतम (उम्र लगभग 40 वर्ष) पुत्र श्री राम, निवासी ग्राम कल्ली पूरब घाघ ने अपने घर के प्रथम तल पर बने कमरे में बिजली के पंखे से दुपट्टे के सहारे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर एकत्र हो गए, जिससे गांव में शोक और दहशत का माहौल बन गया।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई शुरू कर दी है तथा आगे की आवश्यक विधिक प्रक्रिया प्रचलित है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और परिजनों से घटना के संबंध में पूछताछ की।परिजनों से प्राप्त प्रारंभिक जानकारी के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला पारिवारिक विवाद से संबंधित प्रतीत हो रहा है। बताया जा रहा है कि इसी कारण व्यक्ति ने मानसिक तनाव में आकर यह कठोर कदम उठा लिया।

नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, बालिका सकुशल बरामद

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। थाना चिनहट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने अपहृत नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है तथा प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।पुलिस के अनुसार थाना चिनहट पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 223/2026 धारा 87 तथा 137(2) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत वांछित अभियुक्त अमन रावत पुत्र भुल्लू, निवासी नौबस्ता कला थाना चिनहट जनपद लखनऊ, उम्र लगभग 26 वर्ष को 28 अप्रैल 2026 को नेड़ा मोड़ क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।घटना के संबंध में बताया गया कि 27 अप्रैल 2026 को वादी ने थाना चिनहट पर तहरीर देकर सूचना दी थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को अभियुक्त अमन रावत बहला-फुसलाकर शादी करने के उद्देश्य से अपने साथ भगा ले गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चिनहट में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक धनंजय कुमार सिंह द्वारा की जा रही थी।पुलिस टीम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और तलाश अभियान चलाया। इसी क्रम में 28 अप्रैल 2026 को पुलिस ने नाबालिग लड़की को सकुशल बरामद कर लिया। बरामदगी के बाद बालिका का बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180 के अंतर्गत दर्ज किया जा रहा है तथा अन्य आवश्यक साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया जारी है।

गोवध निवारण अधिनियम के तहत स्कूटी राज्य के पक्ष में जब्त करने का आदेश

लखनऊ। पुलिस आयुक्त न्यायालय, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत एक प्रकरण में प्रयुक्त स्कूटी को राज्य के पक्ष में अधिहरण (जब्त) किए जाने का आदेश पारित किया गया है। यह कार्रवाई अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में की गई है।प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना चौक, लखनऊ में पंजीकृत मुकदमा संख्या 244/2025 धारा 325 भारतीय न्याय संहिता, जो विवेचना के दौरान परिवर्तित होकर धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 यथासंशोधित अधिनियम 2020 के अंतर्गत किया गया, से संबंधित वाहन संख्या यूपी 32 एनवी 6783 (स्कूटी) को गोमांस के परिवहन में प्रयुक्त किए जाने का मामला सामने आया था। जांच के दौरान पाया गया कि उक्त स्कूटी का प्रयोग अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए जानबूझकर किया गया था।

बस्ती में धार्मिक स्थलों के विकास हेतु 901 लाख रुपये की 11 परियोजनाएं स्वीकृत

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य योजना के अंतर्गत बस्ती जनपद की विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए 901 लाख रुपये की 11 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए सीएनडीएस को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। कार्यदायी संस्था को निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्य गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ पूर्ण किए जाएं, जिससे श्रद्धालुओं को समय पर सुविधाओं का लाभ मिल सके। इन परियोजनाओं में अधिकांश धार्मिक स्थलों पर बुनियादी सुविधाएं विकसित करने तथा सौंदर्यीकरण के कार्य शामिल हैं।यह जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि हरैया विधानसभा क्षेत्र में स्थित चतुर्भुजी मंदिर लोनिया के पर्यटन विकास के लिए 75 लाख रुपये, महादेवा स्थित

प्राचीन स्वयंभू शिव मंदिर के विकास के लिए 65 लाख रुपये, रूधौली क्षेत्र के विकास खंड भानपुर में बैडवा समय माता मंदिर के विकास के लिए 78 लाख रुपये तथा महादेवा स्थित रामजानकी मंदिर के विकास के लिए 72 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।इसी प्रकार कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में स्थित बाबा भारीनाथ शिव स्थल के पर्यटन विकास के लिए 106 लाख रुपये तथा बस्ती सदर क्षेत्र के बीएमसीटी मार्ग बस्ती कैम्पियरगंज स्थित कोडरा चौराहे पर शिव मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 107 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।पर्यटन मंत्री ने आगे बताया कि बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र के भदेश्वरनाथ गांव में स्थित शिवधाम बाबा भदेश्वरनाथ मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 200 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त रूधौली विधानसभा क्षेत्र में बहुउद्देशीय सुविधाओं के लिए 44 लाख रुपये, महादेवा के ग्राम चंगेरवा गगिया कोहल स्थित प्राचीन शिव मंदिर में बहुउद्देशीय अवस्थापना सुविधाओं के लिए 65 लाख रुपये तथा बस्ती सदर मुख्यालय स्थित कबीर आश्रम मूडघाट में बहुउद्देशीय अवस्थापना सुविधाओं के लिए 45 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है।उन्होंने बताया कि हरैया विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक स्थल तपसीयंधाम आश्रम में बहुउद्देशीय अवस्थापना सुविधाओं के लिए 44 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

लखनऊ में कारोबारी से ठगे 1.15 करोड़ रुपये, एसआईपी और क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने का दिया झांसा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। कृष्णानगर के पूरन नगर निवासी कारोबारी राजेंद्र सिंह चौहान को परिचित ने एसआईपी और क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर मुनाफा कमाने का झांसा दिया। फिर उनके 1.15 करोड़ रुपये हड़प लिए। पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई है।

राजेंद्र ने बताया कि वर्ष 2019 में उनका परिचय हिमांशु गिहर से हुआ था। बातचीत और व्यहवार बढ़ने पर आरोपी ने उन्हें एसआईपी में निवेश कर हर माह दस गुना मुनाफा कमाने का झांसा दिया। लालच में आए पीड़ित ने वर्ष 2021 से 23 के बीच 50 लाख निवेश कर दिए। मगर मुनाफा नहीं मिला। विरोध पर आरोपी ने एसआईपी में घाटा होने की बात कहते हुए दोबारा क्रिप्टो में निवेश करने की बात कही। ठग ने कहा कि क्रिप्टो में निवेश करने पर पहले के

डूबे 50 लाख रुपये भी रिकवर करा देगा। राजेंद्र ने बताया कि अपनी डूबी रकम पाने के लिए उन्होंने वर्ष 2023 से 25 के बीच इस बार 65 लाख रुपये निवेश कर दिए। मगर न तो पहली डूबी रकम रिकवर हुई और न कोई मुनाफा मिला। पीड़ित का आरोप है कि रकम मांगने पर आरोपी अप्रैल 2026 तक टरकाता रहा, फिर धमकाना शुरू कर दिया।

घरवालों के खातों के जरिये निवेश कराई थी रकम

पीड़ित का कहना है कि ठग ने 1.15 करोड़ रुपये खुद न लेकर अपने घरवालों के बैंक खातों में लिए थे। फिर रकम निवेश कराई थी। इतना ही नहीं जिस एप के जरिये उसने रकम निवेश कराई थी उसमें भी अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर लगाया था। इंस्पेक्टर पीके सिंह ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है। साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

दिल्ली में संगठन सुदृढ़ीकरण पर मंथन, कई स्तरों पर फेरबदल कर जनाधार बढ़ाने का दिया निर्देश

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने दिल्ली राज्य इकाई की विस्तृत समीक्षा बैठक में पार्टी संगठन को जमीनी तथा आर्थिक स्तर पर मजबूत बनाने और जनाधार को व्यापक रूप से बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। लंबी चली इस बैठक में पूर्व में दिए गए दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की गहन समीक्षा की गई तथा संगठन के कार्यों का आकलन करते हुए आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।बैठक के दौरान संगठन के जिन पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा संतोषजनक कार्य किए गए, उनके प्रयासों की सराहना की गई, वहीं जहां कार्य अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाए गए, वहां कई स्तरों पर संगठनात्मक फेरबदल किया गया। मायावती ने स्पष्ट निर्देश दिया कि पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरी निष्ठा, अनुशासन और समर्पण के साथ संगठन को मजबूत करने में जुटें तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पूरे मनोयोग से कार्य करें। दिल्ली के वर्तमान राजनीतिक हालात पर चर्चा करते हुए उन्होंने बैठक में प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर कहा कि आमजन के हित, कल्याण और जीवन स्तर से जुड़े मुद्दों को लेकर लोगों में निराशा का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान शासन व्यवस्था आम जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पा रही है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में बहुजन समाज पार्टी आमजन के लिए एक नई उम्मीद के रूप में उभर सकती है, बशर्ते संगठन पूरी लगन और मेहनत के साथ जनता के बीच जाकर अपनी नीतियों और विचारों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करे।

सवालों का सामना करेगी आम आदमी पार्टी?

राजनीति सपने दिखाते हुए लोगों से उन्हें पूरा करने के वायदे करती है, लेकिन लोगों को उन्हीं राजनीतिक दलों के दिखाए सपनों पर भरोसा होता है, जिनकी साख होती है। लोकतंत्र में साख हासिल करने का सबसे बड़ा और जांचा-परखा हथियार आंदोलन ही है। कई बार जनाकांक्षाओं के उफान में आंदोलन से उभरी राजनीति को सफलताएं मिल भी जाती हैं, लेकिन वे लंबे समय तक टिक नहीं पातीं। उनमें बिखराव शुरू हो जाता है। आम आदमी पार्टी के साथ भी क्या ऐसा ही हो रहा है? राघव चड्ढा की अगुआई में आप के दस में से सात सांसदों के बगावती होने और बीजेपी में शामिल होने के बाद कुछ ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं।

इतने सांसदों के एक साथ पार्टी छोड़ने से आप की बौखलाहट स्वाभाविक है। पार्टी की ओर से राघव चड्ढा और उनके साथियों पर आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने ईडी और केंद्रीय एजेंसियों के दबाव में पाला बदल लिया है। इस आरोप के बाद पहला सवाल तो आम आदमी पार्टी पर ही उठता है। ईडी या सीबीआई का डर तो उसे ही होगा, जो भ्रष्टाचारी हो। चूंकि आम आदमी पार्टी का उभार देशव्यापी भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की कोख से हुआ था, भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन देने का उसका वादा भी रहा। ऐसे में अगर उसके सांसद भ्रष्टाचार के डर से पाला बदलते हैं तो इसका मतलब तो यही निकलेगा कि भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करने वाली पार्टी में भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसका सांसद भ्रष्टाचार में कैसे शामिल हो सकता है? अगर शामिल भी हुआ तो उसके नेतृत्व ने इसकी रोकथाम के लिए कोई कारगर कदम क्यों नहीं उठाया। सवाल यह भी उठता है कि क्या भ्रष्टाचार रोकने वाली पार्टी भी दूसरी पार्टियों जैसी क्यों बन गई?

इंदिरा सरकार की जन विरोधी नीतियों और कांग्रेसी सरकारों में भ्रष्टाचार के खिलाफ 1970 के दशक में जेपी आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में शामिल हो रहे लोगों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने जयप्रकाशन नारायण को एक पत्र लिखा था। जेपी आंदोलन का एक लक्ष्य व्यवस्था को बदलना भी था। चंद्रशेखर ने अपने पत्र में आशंका जताई थी कि आंदोलन में शामिल होने वाले नेता व्यवस्था में बदलाव के लिए नहीं, सत्ता के लिए आ रहे हैं। उन्होंने आगे लिखा था कि सत्ता में आने के बाद ये ही नेता व्यवस्था का हिस्सा बन जाएंगे और भविष्य में अपनी-अपनी जातियों के नेता बन जाएंगे। उन नेताओं की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि चंद्रशेखर की आशंका सच हुई। उस आंदोलन से निकलने नेताओं में से ज्यादातर पारिवारिक पार्टियों के नेता हैं और ज्यादातर पर भ्रष्टाचार को लेकर मुकदमे चल रहे हैं। जेपी आंदोलन में उभरे नेताओं का जातीय आधार पर टिकी राजनीति के चलते अस्तित्व बचा हुआ है, लेकिन असम से घुसपैठियों को बाहर निकालने वाले आंदोलन से उभरी पार्टी असम गणपरिषद के नेताओं के बारे में आज देश कितना जानता है? जबकि केजरीवाल की तरह उसके नेताओं ने छात्रावास से निकल कर सीधे सत्ता के गलियारों पर कब्जा कर लिया था।

यह पहला मौका नहीं है कि अन्ना आंदोलन से उभरी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से बड़े नाम निकले हैं। आम आदमी पार्टी के संस्थापकों में शामिल रहे योगेंद्र यादव और मशहूर वकील प्रशांत भूषण को पार्टी ने शुरू में ही या तो निकाल दिया था या वे निकल गए थे। प्रशांत भूषण के पिता शांति भूषण ने आम आदमी पार्टी की स्थापना के लिए भारी रकम दी थी। अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल के साथ कंधा से कंधा भिड़ाकर खड़ी रहीं पूर्व पुलिस अधिकारी किरण बेदी को भी जल्द ही पार्टी से अलग राह चुननी पड़ी थी। पार्टी का शुरू के दिनों से ही बड़ा चेहरा रहीं शाजिया इल्मी भी वहां की बजाय अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे आनंद कुमार हों या फिर कैलाश गहलोत, सबको केजरीवाल की अगुआई वाली पार्टी से अलग राह चुननी पड़ी है।

जब भी किसी दल से कोई नेता बगावत करके नई राह चुनता है, तब वह दल विशेष उसे गद्दार कहता है। राघव चड्ढा की अगुआई में केजरीवाल के खिलाफ बगावत करके नई राह चुनने वाले सांसदों को भी गद्दार कहा जाना कोई नई बात नहीं है। वैसे अपने निजी अहम् या अनदेखी के चलते दलों को छोड़ना या फायदे के लिए दल बदलना भारतीय राजनीति में जाना-पहचाना है। इस लिहाज से देखें तो आम आदमी पार्टी से बगावत होना भी नया नहीं कहा जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस पार्टी की डेढ़ दशक की उम्र भी नहीं हुई, उसके महत्वपूर्ण नेता आखिर क्यों उसे छोड़कर निकल रहे हैं? यह सवाल और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, क्योंकि इस बार पार्टी छोड़ने वाले नेताओं में से राघव चड्ढा और संदीप पाठक तो पार्टी के शुरूआती दिनों से रणनीतिकार और संगठक रहे हैं।

पोषण निगरानी ऐप: कुपोषण के समाधान के लिए डेटा का उपयोग

प्रो. लिंडसे जैक्स

पोषण निगरानी में नियमित रूप से एकत्र किए गए वृद्धि डेटा को अंतिम सिरे पर खड़े व्यक्ति के लिए सार्थक निर्णयों में बदलने की क्षमता है।

हममें से कई लोग अपने डॉक्टरों को इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड में जानकारी दर्ज करते हुए देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये डेटा समय के साथ हमारे स्वास्थ्य की निगरानी करने में मदद करेंगे, जोखिमों की शुरुआत में ही पहचान कर लेंगे और समय पर कार्रवाई को निर्देशित करेंगे। डिजिटल प्रणालियाँ केवल डेटा संग्रह के कारण ही नहीं, बल्कि जानकारी को निर्णय और बेहतर देखभाल में बदलने में मदद करने की वजह से सबसे बेहतर काम करती हैं।

महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2021 में लॉन्च किए जाने के बाद, पोषण निगरानी ऐप ने पोषण सेवा अदायगी डेटा को अधिक कार्रवाई-योग्य बनाने का प्रयास किया है। इसका उद्देश्य केवल डिजिटलीकरण करना नहीं, बल्कि बाल विकास और पोषण सेवाओं को दर्ज करने और समीक्षा करने में अधिक गंभीरता और निरंतरता लाना है।

पोषण निगरानी में नियमित रूप से एकत्र किए गए वृद्धि डेटा को अंतिम सिरे पर खड़े व्यक्ति के लिए सार्थक निर्णयों में बदलने की क्षमता है। मासिक वृद्धि निगरानी—यदि सही ढंग से मापी जाए और लगातार रिकॉर्ड की जाए—तो जोखिम के शुरुआती संकेत प्रदान कर सकती है। एक एकल, निरंतर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, वृद्धि रुझानों को पूरक पोषण उपायों से जोड़ने में मदद कर सकता है, जैसे घर ले जाने वाला राशन, देखभाल करने वालों का परामर्श और गंभीर कुपोषण से पीड़ित बच्चों को स्वास्थ्य केंद्रों में रेफर करना आदि।

इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए, हमें डैशबोर्ड से निर्णय की ओर और गणना से देखभाल की ओर बदलाव करने की आवश्यकता है। अंतर्निहित संकेत, सरल चेकलिस्ट और चेतावनी; आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कमजोर या गंभीर कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए बाद की कार्रवाई करने में मदद कर सकती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा आरसीएच 2.0 पोर्टल के डेटा के साथ एकीकरण, समन्वय की साथ की गयी घर की यात्रा के जरिये रेफरल फॉलो-अप को और भी मजबूत कर सकता है।

वर्तमान में, एकत्रित वृद्धि डेटा एक महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु प्रदान करता है। मापन प्रथाओं और

प्रणाली समर्थन में सुधारों के साथ, यह समय पर निर्णय लेने में भरोसेमंद जानकारी प्रदान कर सकता है। सटीक निर्णय मूलभूत चीज़ों को ठीक करने पर निर्भर करते हैं—भरोसेमंद मापन, सही तकनीकें और कार्यात्मक उपकरण। यदि किसी बच्चे की ऊँचाई या वजन एक महीने में असामान्य रूप से बदलता है, तो प्रणाली को सत्यापन या पुनः मापन का संकेत देना चाहिए। ऐप में शामिल छोटे माइक्रो-वीडियो देखभाल के स्थल पर वजन पैमाने और लंबाई बोर्ड के सही उपयोग को सुदृढ़ कर सकते हैं। समान रूप से महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में माप-संकेत वाले और कार्यात्मक उपकरण मौजूद हों। ये मूलभूत बातें वृद्धि निगरानी डेटा की उपयोगिता को मजबूत करने के लिए आवश्यक हैं।

पोषण निगरानी डेटा का विश्लेषण डैशबोर्ड से निर्णय लेने की प्रक्रिया में बदलाव का भी समर्थन कर सकता है। सबसे पहले, हमें पता होना चाहिए कि कुपोषण की सबसे अधिक संभावना कब होती है—किस उम्र में और वर्ष के किन महीनों में। क्या यह जन्म के समय होता है? या क्या 0 से 3 महीने या 3 से 6 महीने महत्वपूर्ण हैं, जब माताओं को केवल स्तनपान कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है? या यह 6 महीने से 1 साल के दौरान होता है, जब पर्याप्त, उचित और सुरक्षित पूरक आहार की आवश्यकता होती है?

पोषण निगरानी डेटा के विश्लेषण से हमें उन बच्चों के बारे में और ज़्यादा जानने में भी मदद मिल सकती है जो कुपोषण से ठीक हो जाते हैं। क्या कुछ खास ज़िलों के बच्चों में ठीक होने की संभावना ज़्यादा होती है? क्या खरीफ फसल की कटाई वाले महीनों के दौरान बच्चों के ठीक होने की संभावना अधिक होती है? इसी तरह, ऐसे विश्लेषण हमें उन बच्चों के बारे में और भी बहुत कुछ बता सकते हैं जो अपने पूरे बचपन के दौरान बार-बार या लगातार कुपोषण का शिकार होते रहते हैं। क्या ये वे बच्चे हैं, जो जन्म के समय से ही कुपोषण के शिकार थे और बाद में भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए? क्या ये वे बच्चे हैं, जिन्हें घर ले जाने वाला राशन नियमित रूप से नहीं मिल रहा है? इस तरह की जानकारी होने पर, स्थानीय स्तर पर पोषण सेवा अदायगी को बेहतर बनाया जा सकता है।

डेटा पर भरोसा बढ़ाना, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के कार्यभार में कमी लाने के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। प्रणाली में विश्वास बढ़ने के साथ, अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्राथमिक रिकॉर्ड के रूप में ऐप का उपयोग करने की शुरुआत कर रहे हैं। हालांकि, कई जगहों पर, संचार-संपर्क की समस्याओं या अनुपालन आवश्यकताओं के कारण डिजिटल प्रविष्टि के साथ-साथ कागजी रजिस्टर भी रखे जाते हैं। ऑफ़लाइन कार्यक्षमता को मजबूत करना, डेटा की विश्वसनीयता में सुधार करना और डिजिटल-प्रथम कार्यप्रवाह पर स्पष्टता प्रदान करना, सेवा स्थल पर डेटा प्रविष्टि की ओर बदलाव को गति देने और दोहरी रिपोर्टिंग की आवश्यकता को कम करने में मदद कर सकता है। प्रणाली को परिष्कृत करने में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को शामिल करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि ऐप उनके काम में सहायक हो।

पोषण निगरानी ऐप समय पर और सोच-समझकर फ़ैसले लेने में मदद करने वाला एक भरोसेमंद उपकरण है। इसकी असली ताकत जोखिम की जल्द पहचान करने, तेज़ी से बाद की कार्रवाई करने और पोषण सेवाओं के बेहतर तालमेल को सक्षम बनाने में है। आखिरी छोर की ज़मीनी हकीकतों को ध्यान में रखकर बनाया गया और डेटा की गुणवत्ता व इसके इस्तेमाल में हुए लगातार सुधारों से और मज़बूत बनाया गया पोषण निगरानी ऐप, सिर्फ़ एक निगरानी उपकरण ही नहीं, बल्कि पोषण सेवा अदायगी को मज़बूत बनाने का एक सार्थक उपाय भी है।

टिप्पणी

विपक्ष इतना आशंकित क्यों है?

चुनावी लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के मूलभूत सिद्धांत को लेकर विपक्ष इतना आशंकित क्यों है? ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसके अंदेशे निराधार हैं। मगर समस्याएं कहीं और हैं। उनके आधार पर बुनियादी सिद्धांत की अनदेखी गलत कदम होगा।

विधायिका में महिला आरक्षण के लिए संसद के बुलाए गए विशेष सत्र में संभवतः लोकसभा सीटों के परिसीमन से संबंधित विधेयक भी पारित किया जाएगा। केंद्र हर राज्य की मौजूदा सीट को डेढ़ गुना कर देने के फॉर्मूले पर आगे बढ़ता दिख रहा है। मगर इस फॉर्मूले के तर्क को समझना मुश्किल है। संसदीय लोकतंत्र में निम्न सदन की सीटें जनसंख्या के अनुपात में तय होती हैं। परिसीमन भी इसी सिद्धांत से होना चाहिए। मगर अपना सियासी प्रभाव घटने की दक्षिणी राज्यों की आशंका के समाधान के तौर पर केंद्र ने एकरूप फॉर्मूला निकाला है। मगर इससे कोई उद्देश्य हासिल नहीं होगा।

दक्षिण की पार्टियां यह कहते हुए इस फॉर्मूले का विरोध कर रही हैं कि इससे उत्तरी राज्यों और उनकी लोकसभा सीटों की संख्या में फासला और बढ़ जाएगा। कांग्रेस भी अपनी राजनीतिक गणना के तहत इस दलील के साथ खड़ी है। अतः ये सवाल अहम हो जाता है कि आखिर चुनावी लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के मूलभूत सिद्धांत को लेकर विपक्ष इतना आशंकित क्यों है? ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये अंदेशे निराधार हैं। मगर उनकी जड़ें नरेंद्र मोदी सरकार के संवाद और सहमति को ठुकराने और अपनी सोच को बुल्डोजरी तरीके से लागू करने में छिपी हैं। केंद्र ने राष्ट्रीय विकास परिषद एवं राष्ट्रीय एकता परिषद जैसे संवाद के मंचों को समाप्त कर दिया है।

बाकी संस्थाओं को नियंत्रित करने की उसकी कोशिशों ने उससे असहमत तबकों और क्षेत्रों में विपरीत भावनाएं पैदा की हैं। उनका असर परिसीमन से जुड़ी बहस पर देखा गया है। संसद का सत्र भी बिना आम-सहमति बनाए उस समय बुलाया गया है, जब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव का प्रचार चरम पर होगा। स्पष्टतः वहां के सांसदों के लिए इससे मुश्किल खड़ी होगी। मगर, इस पृष्ठभूमि के कारण प्रतिनिधित्व के बुनियादी सिद्धांत की अनदेखी गलत परिपाटी को जन्म देगी। परिपक्व लोकतांत्रिक देशों में जनता के सदन को संतुलित करने के लिए अधिकार-प्राप्त उच्च सदन की व्यवस्था की गई है। भारत में ये व्यवस्था आंशिक रूप से ही कारगर है। बहरहाल, समस्या जहां है, उससे कहीं अलग हल ढूंढना नई समस्याओं को जन्म देगा।

ब्लॉग

देश में संसद की पवित्रता की बहस

अजीत द्विवेदी

इतनी लंबी भूमिका की जरुरत इसलिए थी क्योंकि इस समय देश में संसद की पवित्रता की बहस चल रही है। बहुत सारे लोगों की भावनाएं इस बात से आहत हैं कि राहुल गांधी संसद की सीढ़ियों पर समोसे खा रहे थे और चाय पी रहे थे।

भारत में किसी भी चीज को नष्ट करने के कई तरीकों में से एक तरीका यह है कि उसे पवित्र बना दिया जाए। उसे पूजा के योग्य बना दिया जाए। जैसे ही हमारे यहां कहा जाए कि अमुक चीज तो पवित्र है और हम उसकी पूजा करते हैं तो समझ लें कि वह चीज ज्यादा समय तक नहीं रहने वाली है। उसका नष्ट होना अवश्यम्भावी है। मिसाल के तौर पर भारत में नदियों की स्थिति देखी जा सकती है। नदियों को भारत में माता का दर्जा दिया जाता है और पूजा की जाती है लेकिन पूजा करने वाला व्यक्ति भी नदी की साफ सफाई और उसकी पवित्रता का ध्यान नहीं रखता है। सारा कचरा नदियों में जाता है, लोगों के घरों के गंदे नाले नदियों में जाते हैं, औद्योगिक इकाइयों का कचरा नदियों में गिरता है, इसके अलावा और क्या क्या होता वह लिखने की जरुरत नहीं है। सरकारें हजारों करोड़ रुपए खर्च करती हैं और किसी भी नदी की सफाई नहीं हो पाती है।

ऐसे ही हमलोगों ने पहाड़ों को पूजना शुरू किया और अपने लालच में उनकी ऐसी खुदाई शुरू की या पहाड़ काट कर ऐसे निर्माण शुरू किए कि हर पर्वत श्रृंखला अस्तित्व का संकट झेल रही है। इसी तरह भारत में पेड़ों की पूजा होती है और फिर ऐसी अंधाधुंध कटाई होती है कि लाखों, करोड़ों हेक्टेयर में फैले जंगल समाप्त हो गए। हम अपनी देवियों की पूजा करते हैं और हमारे घरों में स्त्रियों की क्या स्थिति है यह राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं। ऐसी अनेक मिसालें और भी दी जा सकती हैं। लेकिन विषय को समझने के लिए इतना पर्याप्त है।

इतनी लंबी भूमिका की जरुरत इसलिए थी क्योंकि इस समय देश में संसद की पवित्रता की बहस चल रही है। बहुत सारे लोगों की भावनाएं इस बात से आहत हैं कि राहुल गांधी संसद की सीढ़ियों पर समोसे खा रहे थे और चाय पी रहे थे। असल में कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने लोकसभा से निलंबित सांसदों के साथ मकर द्वार के पास बैठ कर समोसे खाए थे और चाय पी थी। इसे लेकर भाजपा के सांसदों ने नाराजगी जताई तो देश के दो सौ से ज्यादा कथित गणमान्य लोगों के चि_ी लिखने की भी खबर आई, जिसमें राहुल गांधी के व्यवहार को संसद की गरिमा के विरूद्ध बताया गया और उनकी आलोचना की गई। इससे पहले भाजपा के सांसदों ने तृणमूल के एक बुजुर्ग सांसद की शिकायत स्पीकर से की थी, जिसमें कहा गया है कि वे संसद परिसर में सिगरेट पी रहे थे। संसद के अंदर ई सिगरेट पीने की शिकायत भी की गई। ऐसे ही कांग्रेस की एक सांसद कुत्ता लेकर संसद परिसर में आ गई थीं तो उसकी भी बड़ी आलोचना हुई थी।

इसमें से ज्यादातर घटनाएं सामान्य मानवीय व्यवहार से जुड़ी हैं। हो सकता है कि किसी सांसद के सामान्य मानवीय व्यवहार से कोई दूसरा सदस्य आहत हो जाए। जैसे फिल्म अभिनेत्री से सांसद बनीं भाजपा की एक नेता को राहुल गांधी का व्यवहार 'टपोरी जैसा लगता है और उनका दावा है कि राहुल गांधी को देख कर महिला सांसद असहज हो जाती हैं। ऐसे ही राहुल गांधी या किसी अन्य सांसद के सीढ़ियों पर खाना खाने से या संसद परिसर में सिगरेट पीने से कुछ लोगों की भावनाएं आहत होती हों। लेकिन इससे संसद की गरिमा और पवित्रता नष्ट होती है, ऐसा नहीं माना जा सकता है। आखिर संसद के अंदर भी खाने की कैंटीन है। लोग खाना खाते हैं। कुछ दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने संसद की सीढ़ियों पर पूरी रात धरना दिया तो वे उन्होंने वही खाना खाया और वही पर सोए। पहले भी ऐसा होता रहा है। इसलिए ऐसी बातों का मुद्दा बना कर विपक्ष के नेताओं को गैरजिम्मेदार, अगंभीर और गरिमामय आचरण नहीं करने का दोषी तो बताया जा सकता है लेकिन इसे संसद की गरिमा और पवित्रता के विरूद्ध बताना उचित नहीं है।

संसद की गरिमा और पवित्रता ऐसी चीजों से तय नहीं होती हैं। संसद की गरिमा और पवित्रता इससे तय होती है कि संसद में किस तरह के विधायी कामकाज होते हैं। देश के 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का भाग्य तय करने वाले लोग वहां बैठते हैं, वे कैसे इतने लोगों की किस्मत तय करने वाले फैसले करते हैं, इससे संसद की गरिमा तय होती है। संसद के सदस्य सदन के अंदर किस तरह का आचरण करते हैं, किस तरह संवाद करते हैं, किस तरह की बहस करते हैं इससे तय होगा कि संसद का कितना सम्मान है और कितनी गरिमा है। संसद के संचालन में पक्ष और विपक्ष के बीच समन्वय बनता है या नहीं या सत्तापक्ष की ओर से विपक्ष को अपनी बात रखने का स्पेस दिया जाता है या नहीं इससे तय होगा कि संसद कितनी पवित्र है। इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सांसदों का आचरण शामिल है।

संसद में जरूरी मसलों पर चर्चा नहीं हो। 140 करोड़ लोगों की किस्मत तय करने वाले विधेयक मिनटों में बिना किसी बहस के पास हो जाएं। विपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया जाए या बोलने से रोका जाए। विधेयकों को संसदीय समितियों के सामने नहीं भेजा जाए या संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स को गंभीरता से नहीं लिया जाए। संसदीय समितियों में बहुमत के दम पर हर बार सरकार के पक्ष को स्वीकार किया जाए और विपक्ष की मांग खारिज हो। विधेयकों पर विपक्ष की आपत्तियों को बिना चर्चा के खारिज कर दिया जाए। तब संसद की गरिमा प्रभावित होती है। कानून की गुणवत्ता और उसके व्यापक असर में कोई कमी रह जाए तो संसद की गरिमा पर आंच आती है। इसकी बजाय अगर चर्चा इस दिशा में चली जाए कि अमुक नेता टीशर्ट पहन कर सदन में आता है या अमुक नेता सीढ़ियों पर बैठ कर खा रहा था तो समझ लेना चाहिए कि कुछ बुनियादी गड़बड़ी है। ऐसे मामले आमतौर पर ध्यान भटकाने या किसी नेता की साख बिगाड़ने के लिए उछाले जाते हैं। उनका संविधान की ओर से विधायिका के लिए निर्धारित भूमिका से कोई लेना देना नहीं होता है।

'काश भाई को साथ ले आता तो नहीं...', ट्रिपल मर्डर में मनीष के चचेरे भाई ने बयां की घटना से पहले की कहानी

आर्यावर्त संवाददाता

बुलंदशहर। अगर मैं उस रात मनीष भाई का हाथ पकड़कर खींच लाता, तो आज हमारे घर के आंगन में चीखें नहीं, बल्कि भाइयों की हंसी गूंज रही होती। मेरी एक चूक ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं। यह कहते हुए उधम सिंह सैनी का गला रुंध गया और आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा।

बुलंदशहर में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद उधम सिंह बोले, शनिवार की उस काली रात ने हमारे परिवार के तीन सदस्यों को हमसे छीन लिया, अब पीछे रह गया है तो बस कभी न खत्म होने वाला पछतावा। उधम सिंह ने बताया कि वह और उसका चचेरा भाई मनीष शनिवार रात को एक शादी समारोह में शिरकत कर घर लौट रहे थे।

रात के करीब साढ़े नौ बज रहे थे, तभी मनीष के मोबाइल फोन की घंटी बजी। फोन पर मिली सूचना ने दोनों के माथे की शिकन बढ़ा दी। जिम पर अमरदीप का झगड़ा होने की सूचना मिलते ही बिना एक पल गंवाए, दोनों भाई बाइक से सीधे जिम पहुंचे।

वहां अमरदीप और जीतू सैनी के बीच बहस हो रही थी। मनीष और उधम ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। उस वक्त लगा कि विवाद टल गया है, लेकिन किसे पता था कि इतनी बड़ी घटना हो जाएगी।

उधम ने बताया कि जब हमलावर जीतू और मयंक वहां से चले गए, तो माहौल सामान्य दिखने लगा था। मोहल्ले के कुछ अन्य युवक भी वहां मौजूद थे। उधम के पास उसके बड़े भाई धर्म का बार-बार फोन आ रहा था कि रात काफी हो गई है, घर आ जाओ। इस दौरान मनीष ने उधम से कहा कि तू घर निकल, मैं अमरदीप और आकाश को लेकर आता हूं। उधम ने बताया कि उसने भाई मनीष की बात मान ली और घर की ओर चल दिया लेकिन महज 15 मिनट बाद ही फोन आया कि सब खत्म हो गया। उधम ने बताया कि जिम के अंदर उस वक्त मनीष, अमरदीप, आकाश, जिम संचालक रूपेश और अमरजीत ही बचे थे, तभी हमलावरों ने लौटकर मौत का नंगा नाच खेला। जब पहुंचे तो मौके पर पहुंचे तो मनीष, अमरजीत और आकाश के शव पड़े थे।

उधम को मलाल है कि काश उसने मनीष की बात न मानी होती और उसे अपने साथ ले आता तो सबकी जान बच जाती। मनीष सबसे बड़े ताऊ प्रेम सिंह का बेटा था। अमरदीप और आकाश दूसरे नंबर के ताऊ सरूप सैनी के परिवार से थे। उधम के पिता नन्हें सैनी तीसरे नंबर के भाई हैं।

जीतू सैनी समेत सात की तलाश में दिल्ली-हरियाणा, कई जनपदों में ताबड़तोड़ दबिश

बुलंदशहर के खुर्जा में हुए ट्रिपल मर्डर के बाद मुख्य आरोपी जीतू समेत कुल सात आरोपी अभी फरार हैं और पुलिस को चकमा दे रहे हैं। फरार मुख्य आरोपी जीतू सैनी और उसके सात साथियों को दबोचने के लिए पुलिस ने 35 से अधिक स्थानों पर दबीश दे चुकी है।

जिम हत्याकांड में कोतवाली प्रभारी समेत चार निलंबित

हालांकि, सोमवार को पुलिस ने तीन गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया है। बाकी बदमाशों की तलाश में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पुलिस की छह टीमें लगातार छापा मार रही हैं। उधर, तीन लोगों की हत्या के मामले में एसएसपी ने कोतवाली प्रभारी समेत चार लोगों को निलंबित किया। सीओ खुर्जा शोभित कुमार ने बताया कि सरूप सैनी की तहरीर पर नामजद 10 आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। रविवार शाम को पुलिस ने मयंक सैनी, रूपेश सैनी और नरेश उर्फ देवा को गिरफ्तार किया था। सोमवार को इन्हें न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। हालांकि, घटना का मुख्य सूत्रधार जीतू सैनी, रवि, रिंकू, भारत, मनीष, अनुज और सौरभ उर्फ सीटू अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं।

पुलिस का कहना है कि गोली चलाने वाले, साजिश रचने वाले और तमाशबीन रहने वाले, सभी बराबर के दोषी हैं और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जांच को पुख्ता बनाने के लिए पुलिस ने सुभाष मार्ग पर लगे लगभग 70 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है।

इन फुटेज के आधार पर ही आरोपियों की पहचान सुनिश्चित की गई और उनके भागने के रास्तों का पता लगाया गया। जिले की छह से सात सर्विलांस टीमें बदमाशों की फोन कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रेस करने में जुटी हैं। निरीक्षकों की टीम को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे उन लोगों की गतिविधियों पर नजर रखें जो फरार आरोपियों के संपर्क में हैं।

> फरार आरोपियों की तलाश में दबिशें जारी हैं, कुछ अहम सुराग मिले हैं, जल्द ही अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर राजफाश कर दिया जाएगा।
>
> **- अंतरिक्ष जैन, एसपी देहात बुलंदशहर।**

रिश्तेदारों से पूछताछ कर रहीं विशेष टीमें

खुर्जा कोतवाली स्तर से दो विशेष टीमों का गठन किया गया है। प्रत्येक टीम में दो दारोगा, दो महिला सिपाही और चार पुरुष सिपाही शामिल हैं। यह टीमें आरोपियों के रिश्तेदारों, परिचितों और पारिवारिक सदस्यों के घरों पर जाकर पूछताछ कर रही हैं। पुलिस का मुख्य उद्देश्य इन रिश्तेदारों के माध्यम से आरोपियों के संभावित ठिकानों का पता लगाना है।

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना में वांछित आठ आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर खुर्जा नगर कोतवाली प्रभारी प्रेम चंद शर्मा को निलंबित किया गया। चौकी प्रभारी व बीट आरक्षी के कमजोर आसूचना संकलन एवं क्षेत्र में हो रही गतिविधियों में अनभिज्ञता और क्षेत्र में चल रहे क्रियाकलापों की जानकारी न होने के कारण इतनी बड़ी घटना घटित हुई। जिस कारण चौकी प्रभारी बुर्ज उस्मान प्रीतम सिंह, मुख्य आरक्षी समीम अहमद व आरक्षी पारस यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

तिहरे हत्याकांड में शामिल एक आरोपी के पैर में पुलिस ने मारी गोली, जेल भेजा

खुर्जा के सुभाष मार्ग पर शनिवार रात जिम में हुए तिहरे हत्याकांड के आरोपी मयंक सैनी ने सोमवार तड़के पुलिस अभिरक्षा से भागने की कोशिश की। इस दौरान उसने पुलिस पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटना में शामिल तीन आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार किया था। शनिवार रात आरजेएस फिटनेस जिम में जन्मदिन की पार्टी के दौरान हुए विवाद के बाद अंधाधुंध फायरिंग कर मनीष सैनी (32), उनके चचेरे भाई अमरदीप (35) और भतीजे आकाश (20) की हत्या कर दी गई थी। एक ही परिवार के तीन युवकों की हत्या से पूरा जिला थर्रा गया था।

सीओ खुर्जा शोभित कुमार ने बताया कि रविवार देर शाम को पुलिस ने हत्याकांड के आरोपी जिम संचालक रूपेश सैनी, मयंक सैनी और नरेश उर्फ देवा को गिरफ्तार किया था। सोमवार सुबह पुलिस टीम मयंक सैनी को उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद कराने के लिए अगवाल पुल के पास ले गई थी। यहां मयंक ने छिपाया हुआ तमंचा निकाला, उसने पुलिस टीम पर फायर कर भागने का प्रयास किया। पुलिस ने खुद को बचाते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक गोली मयंक के पैर में लगी। पुलिस ने घेराबंदी कर उसे घायल अवस्था में फिर से दबोच लिया। उसके पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं।

पुलिस ने सोमवार दोपहर को मुठभेड़ में घायल मयंक सैनी समेत तीनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय में पेश किया। यहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले के अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

पत्रकार हत्याकांड 22 माह बीता, नहीं मिला न्याय

आर्यावर्त संवाददाता

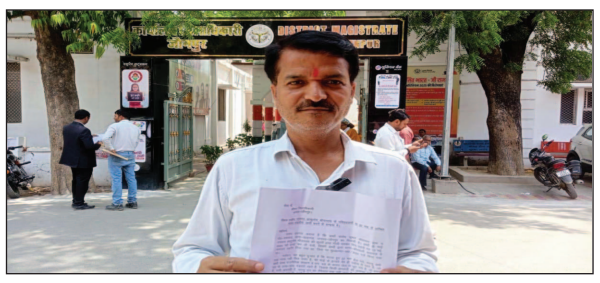

जौनपुर। जनपद में चर्चित पत्रकार हत्याकांड के 22 माह बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय और सुरक्षा के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। हैरानी की बात यह है कि मामले के सभी आरोपी जमानत पर जेल से रिहा हो चुके हैं, जबकि अपनी सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस मांग रहे परिवार की फाइलें अब भी दफ्तरों में धूल फांक रही हैं। थाना शाहगंज क्षेत्र के सबरहद गांव निवासी पत्रकार आशुतोष श्रीवास्तव की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से ही परिवार दहशत में जी रहा है। मृतक के बड़े भाई संतोष श्रीवास्तव और उनके परिजनों ने अपनी जान-माल की सुरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस हेतु आवेदन किया था। संतोष श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी पीड़ा साझा की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया था। संबंधित विभाग द्वारा जांच व निरीक्षण की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई, लेकिन इसके बावजूद आज तक लाइसेंस जारी नहीं किया गया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि फाइलें विभिन्न स्तरों पर लंबित पड़ी हैं और बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल रहा है। इस वजह से परिवार को लगातार मानसिक तनाव और असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है।संतोष श्रीवास्तव ने जिलाधिकारी से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच कराई जाए और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाए, ताकि शस्त्र लाइसेंस जारी कर परिवार को सुरक्षा प्रदान की जा सके। यह मामला एक बार फिर प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है, जहां एक ओर गंभीर आपराधिक घटनाओं के पीड़ित सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी प्रक्रियाओं की धीमी रफ्तार उनके भरोसे को कमजोर कर रही है।

खाद्य सुरक्षा विभाग की सुस्ती न बन जान जाय मुसीबत

जौनपुर। जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यप्रणाली षिथिल पड़ गयी है। कहीं भी जांच पड़ताल होता नहीं दिख रहा है कही इसकी वजह से बड़ी घटना को अंजाम न दे जो मुसीबत बन जाय। शहरी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा को लेकर जहां विभाग की जिम्मेदारी सबसे अहम मानी जाती है, वहीं आरोप लग रहे हैं कि जांच और निरीक्षण के नाम पर केवल औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। शहर में घनी आबादी वाले इलाकों में संचालित नाश्ता, होटल और खान-पान के प्रतिष्ठानों पर विभागीय कार्रवाई को लेकर आम जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटे दुकानदारों पर तो विभाग द्वारा कार्रवाई दिखती है, लेकिन बड़े और नामचीन होटल व ढाबा संचालकों के खिलाफ सख्त कदम कम ही नजर आते हैं। यह भी आरोप सामने आ रहे हैं कि कुछ मामलों में 'सुविधा शुल्क' के बाद निरीक्षण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देकर मामला शांत कर दिया जाता है।

मैनपुरी में भयानक हादसा : पिकअप ने रौंदे बाइक सवार, भाई-बहन और जीजा की मौत ; अंतिम संस्कार में जा रहे थे तीनों

आर्यावर्त संवाददाता

मैनपुरी। मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र में पिकअप वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। इससे बाइक पर सवार बहन भाई और जीजा की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

जानकारी के अनुसार जनपद फिरोजाबाद के मोहल्ला ककरऊ निवासी धर्मेंद्र सिंह 50 पुत्र रामचरण अपनी पत्नी बेबी और जनपद मैनपुरी के गांव तावेपुर निवासी साले संजय सिंह 40 के साथ गांव ताबेपुर मैनपुरी जा रहे थे। तीनों को गांव ताबेपुर में बेबी के ताऊ सादौ सिंह की अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे थे।

जैसे ही बाइक सवार थाना मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र में शीतला माता मंदिर के पास पहुंचे वैसे ही पिकअप वाहन ने टक्कर मार दी। इससे मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। पुलिस ने तीनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। घटना की सूचना मिलते ही एसपी गणेश साहा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

एनएच-34 पर डंपर और मारूति वैन की टक्कर, चार बरातियों की मौत, तीन की हालत नाजुक

आर्यावर्त संवाददाता

हमीरपुर। हमीरपुर जिले में नेशनल हाईवे-34 पर छिरका के पास सोमवार देर रात डंपर और मारूति वैन की आमने-सामने टक्कर में चार बरातियों की मौके हो गई जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी मौदहा पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

कुरारा थानाक्षेत्र के ग्राम डामर से कुशवाहा समाज की बरात कबरई थानाक्षेत्र के ग्राम खड्डी पहरा (महोबा) जा रही थी। बरात में शामिल कुछ लोग मारूति वैन से जा रहे थे। जैसे ही वाहन छिरका के पास पहुंचा तभी सामने से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में वैन के परखच्चे उड़ गए और उर्दना निवासी मोहन (20), तिंदुही निवासी आशीष (30), डामर निवासी कमलेश और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई।

ये लोग हुए हैं घायल

वहीं रोहित (19) निवासी तिंदुही, दिलीप (24) निवासी उर्दना और बाबूजी निवासी डामर घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मृगांक शेखर पाठक, क्षेत्राधिकारी मौदहा राजकुमार पांडे, कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार समेत पुलिस बल मौके पर पहुंच गया।

शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भिजवाया। क्षेत्राधिकारी मौदहा राजकुमार पांडे ने बताया कि छिरका के पास मारूति वैन और डंपर के बीच टक्कर हुई है, जिसमें चार लोगों की मौत हुई है और तीन लोग घायल हैं। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

कार की टक्कर से नाराज मनबढ़ों ने युवा उद्यमी को पीटकर मार डाला, ईंट से कूंच दिया सिर, बाहर आईं आंखें

आर्यावर्त संवाददाता

वाराणसी। वाराणसी के फूलपुर थाना इलाके के भरथरा (घमहापुर) में रविवार की रात कारखाने से घर लौट रहे कार सवार मनीष सिंह (36) की उनके घर से 100 मीटर दूर पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। कार के धक्के से घायल महिला के परिजनों और मनबढ़ों ने मनीष का सिर ईंट से कूंच दिया। आंखें बाहर निकल आईं और शरीर के हर अंग को चोट पहुंचाई। पुलिस ने आठ नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दो आरोपियों हरिश्चंद्र और योगेंद्र को गिरफ्तार किया गया है। 11 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। एहतियातन गांव में फोर्स व पीएसी तैनात की गई है।

भरथरा गांव निवासी मनीष सिंह की घर के पास ही दोना-पत्तल की फैक्टरी है। कारखाने से रात 10 बजे कार से मनीष घर लौट रहे थे। गांव में प्रवेश करते समय ही महिला बिंदु देवी अपने घर के सामने बर्तन धो रही थीं। कार से बिंदु को धक्का लग गया और वह घायल हो गईं। इस बीच ग्रामीणों ने मनीष को घेर लिया और कुछ मनबढ़ों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। लाठी-डंडे और ईंट से लगातार वार किया। ईंट से सिर कूंच डाला, जिससे उनकी आंखें बाहर आ गईं। हाथ पैर कई जगह से फ्रैक्चर हो गए। परिजनों को जानकारी हुई तो मौके पर पहुंचे और मरणासन्न अवस्था में मनीष को लेकर पीएचसी बसनी ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने बीएचयू रेफर कर दिया। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में चिकित्सकों ने मनीष को मृत घोषित कर दिया। युवा उद्यमी की हत्या की सूचना मिलते ही गोमती जोन के एडीसीपी नृपेंद्र कुमार, कार्यवाहक पिंडरा एसीपी अंजनी राय, फूलपुर, बड़ागांव समेत आसपास थानों की फोर्स और पीएसी भी पहुंच गई। फूलपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया।

> दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की दो टीमें गठित की गई हैं। एहतियातन गांव में फोर्स तैनात की गई है।
>
> - नृपेंद्र कुमार, एडीसीपी गोमती जोन

एसओजी के सिपाही की छीनी पिस्टल बनाया बंधक, प्राथमिकी दर्ज

मनीष सिंह हत्याकांड में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सोमवार की रात आठ बजे के बाद खालिसपुर स्थित राजभर बस्ती में दबिश देने गई क्राइम ब्रांच की टीम को बस्ती वालों ने बंधक बना लिया। गलतफहमी में ग्रामीणों ने एसओजी के एक सिपाही की पिस्टल छीन ली।

एक सिपाही की पिटाई भी की गई। फूलपुर इंस्पेक्टर अतुल कुमार सिंह फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और एसओजी के दो सिपाहियों को छुड़ाया। वहीं आरोपी युवक भाग निकला। दबिश के दौरान पुलिस पर हमला और सरकारी कार्य में बाधा के आरोप में 60 अज्ञात के खिलाफ फूलपु फूलपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। फूलपुर थाना क्षेत्र के भरथरा में मनीष सिंह की हत्या के आरोपियों की लोकेशन खालिसपुर गांव में मिली तो एसओजी सादे वेश में दबिश देने रात आठ बजे गांव में पहुंच गई। इस बीच ग्रामीणों को लगा कि मनीष सिंह के परिजन जबरन उठाने आए हैं। एक आरोपी को एसओजी ने पकड़ा तो 100 से अधिक ग्रामीणों ने घेर लिया। जबरन उठाने की गलतफहमी में एसओजी टीम से उलझ गए और मारपीट पर उतारू हो गए। सूत्रों के मुताबिक एक एसओजी का जवान भाग निकला और दो पकड़ में आ गए। इंस्पेक्टर अतुल कुमार सिंह ने बताया कि ग्रामीणों ने गलतफहमी में एसओजी टीम के साथ बदसलूकी की है।

594 KM एक्सप्रेसवे का पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन, मेरठ-प्रयागराज का सफर होगा सुपरफास्ट

आर्यावर्त संवाददाता

मेरठ। मेरठ से प्रयागराज से मेरठ के बीच 594 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर देश के विकास का पहिया 29 अप्रैल यानी कल (बुधवार) से दौड़ने लगेगा। यूपी के इस सबसे लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को उत्तराखंड के हरिद्वार तक जोड़ा जाएगा। फिलहाल छह लेन वाले इस एक्सप्रेसवे को आने वाले समय में आठ लेन का किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे।

36,230 करोड़ रुपये की लागत से बनकर तैयार गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिले और 519 गांवों से होकर गुजरेगा। इसमें मेरठ, बुलंदशहर, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जैसे बड़े महानगर भी शामिल हैं। एक्सप्रेसवे पर 3.5 किमी लंबा एयरस्ट्रिप भी बनाया गया है। इस पर भारतीय वायु सेना के लड़ाकू विमान भी आपात लैंडिंग कर सकेंगे।

हापुड़ के ब्रजघाट में गंगा पर एक किमी और इससे आगे रामगंगा पर 720 मीटर लंबे पुलों से इस एक्सप्रेसवे को गुजारा गया है। दोनों नदियों के ऊपर से गुजरते समय लोगों को अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। इसमें 381 अंडरपास, 14 मुख्य पुल, 126 छोटे पुल और 929 पुलिया शामिल हैं।

बिजौली (मेरठ) से चांदनेर (हापुड़) 48.9 किमी, चांदनेर (हापुड़) से मिर्जापुर डूंगल (अमरोहा) 30 किमी,मिर्जापुर डूंगल (अमरोहा) से नगला बरहा (बदायूं) 50.7 किमी,नगला बरहा (बदायूं) से बिनावर (बदायूं) 52.1 किमी,बिनावर (बदायूं) से दरी गुलऊ (शाहजहांपुर) 46.7 किमी, दरी गुलऊ (शाहजहांपुर) से उबरिया खुर्द (हरदोई) 52.9 किमी है।

उबरिया खुर्द (हरदोई) से इकसाई (हरदोई) 52.4 किमी, इकसाई (हरदोई) से रैया माओ (उन्नाव) 50.2 किमी, रैया माओ (उन्नाव) से सरसों (उन्नाव) 53.1 किमी,सरसों (उन्नाव) से तेरुखा (रायबरेली) 51.8 किमी, तेरुखा (रायबरेली) से नौढ़िया (प्रतापगढ़) 52 किमी, नौढ़िया (प्रतापगढ़) से जूड़ापुर दांदू (प्रयागराज) 53 किमी है।

जिला स्थान एवं कनेक्शन इंटरचेंज का प्रकार

मेरठ -

मेरठ-हापुड़ सड़क पर बिजौली - इंटरचेंज मुख्य

हापुड़ - गढ़मुक्तेश्वर ,एनएच 9, दिल्ली-मुरादाबाद सड़क - डायमंड इंटरचेंज

बुलंदशहर - खुर्जा,बुलंदशहर लिंक जेवर एयरपोर्ट और इंडस्ट्रियल हब के लिए - डायमंड इंटरचेंज

अमरोहा - हसनपुर, मुरादाबाद- संभल के लिए कनेक्टिविटी - रैंप टोल एवं एंट्री पॉइंट

बदायूं - बिनावर, एसएच-51 लिंक सड़क के पास - मुख्य टोल और एग्जिट

शाहजहांपुर - दरी गुलऊ, एनएच 30 और हवाई पट्टी - इंटरचेंज और एयरस्ट्रिप पॉइंट

हरदोई - उबरियाखुर्द और इकसाई - मल्टीपल एंट्री एवं एग्जिट पॉइंट

उन्नाव - रैया माओ, लखनऊ-कानपुर के यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण - प्रमुख इंटरचेंज

रायबरेली - तेरुखा और लालगंज क्षेत्र - सुल्तानपुर और लखनऊ सड़क कनेक्ट

प्रयागराज - जूड़ापुर दांदू, एनएच 19, पुराना एनएच-2 के पास - मुख्य टर्मिनल अंतिम बिंदु

गंदगी का अंबार, ग्रामीणों में भारी रोष

जौनपुर। विकासखंड बक्सा के अंतर्गत उटरू खुर्द गाँव में विकास कार्यों की पोल खुलती नजर आ रही है। यहाँ पिछले 3-4 महीनों से खुली पड़ी नालियाँ और जलजमाव की समस्या ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है। गाँव के निवासी सनी कुमार गुप्ता, राधेश्याम सेठ, पूर्व ब्लाक प्रमुख बक्सा सुल्तान ,शब्बीर अहमद, रामलाल प्रजापति, लोटन राम प्रजापति , कृपाशंकर यादव, रामकुमार निगम, कुलदीप निगम, मोहम्मद अनीस, मोहम्मद तारिक, बुल्ले, रहीम, सद्दाम, पंकज सहित बुजुर्गों का कहना है कि नालियों का निर्माण कार्य अधर में लटका हुआ है। जल निकासी की कोई व्यवस्था न होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है, जिससे गाँव में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है।ग्रामीणों ने ब्लॉक प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कागजों पर कई बार नाली निर्माण के लिए पैसा निकाला जा चुका है।

विश्वविद्यालय में पुस्तकों की खरीद में 33 करोड़ की धांधली

आर्यावर्त संवाददाता

जौनपुर। पूर्वांचल विश्वविद्यालय एक बार फिर वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सुर्खियों में है। वर्ष 2017 से 2022 के बीच पुस्तकों की खरीद में करीब 33 करोड़ 29 लाख रुपये की धांधली का मामला सामने आया है। इस गंभीर मामले पर राजभवन ने विश्वविद्यालय प्रशासन से नौ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा है।यह मामला स्वामी विवेकानंद केंद्रीय पुस्तकालय में पुस्तक खरीद को लेकर मिली शिकायत के बाद उजागर हुआ। शिकायतकर्ता उद्देश्य सिंह ने राजभवन और कुलपति को पत्र भेजा था, जिसके आधार पर विश्वविद्यालय ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कई महत्वपूर्ण खामियां सामने आईं।जांच में पाया गया कि पुस्तक खरीद के दौरान न तो निर्धारित टेंडर प्रक्रिया का पालन किया गया और न ही अधिक छूट प्राप्त करने के लिए कोई प्रतिस्पर्धी प्रयास हुआ। विश्वविद्यालय ने स्वयं स्वीकार किया कि 10 प्रतिशत से अधिक छूट हासिल करने के लिए कोई पहल नहीं की गई। पुस्तकालय समिति की बैठकों में भी इस संबंध में कोई प्रस्ताव दर्ज नहीं मिला। सबसे बड़ी लापरवाही यह रही कि करोड़ों रुपये की खरीद से पहले वित्त समिति और कार्य परिषद से बजट प्रस्ताव पारित नहीं कराया गया। कई मामलों में तो वित्त समिति को इस बड़े खर्च की जानकारी तक नहीं थी।जानकारी के अनुसार, खरीदी गई पुस्तकों का न तो उचित रिकॉर्ड तैयार किया गया और न ही उनकी बारकोडिंग की प्रक्रिया पूरी की गई। नियमानुसार, पुस्तकों को सॉफ्टवेयर में दर्ज करना अनिवार्य होता है, जिसका पालन भी नहीं किया गया। कोविड-19 महामारी के दौरान विश्वविद्यालय बंद रहने के बावजूद बड़ी संख्या में किताबें खरीदी गईं। जांच में यह भी सामने आया कि कई पुस्तकें बिना आवश्यकता के खरीदी गईं और उनकी उपयोगिता का आकलन नहीं किया गया, जिससे विद्यार्थियों को उनका लाभ नहीं मिल सका। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में इन सभी खामियों को स्वीकार किया है। अब विश्वविद्यालय सभी बिंदुओं पर जवाब तैयार कर राजभवन को भेजने की प्रक्रिया में है। इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई राजभवन के निर्देशों पर निर्भर करेगी। मामले की जानकारी देते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. वंदना सिंह ने बताया कि इस तरह का मामला सामने आया है राज भवन से रिपोर्ट मांगी है और जिस पर आरोप लगा है उनसे भी स्पस्टीकरण मांगा गया है। मामले की जांच की जा रही है रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

शरीर में बढ़ेगा खून, करीना कपूर की डायटीशियन ने बताए 7 आसान तरीके

अच्छा खाना यानी हेल्दी लाइफ।। ज्यादातर लोगों में बीमारियों की वजह खानपान का सही न होना होता है। ऐसी ही एक हेल्थ प्रॉब्लम है एनीमिया यानी खून की कमी। आप भी अगर इससे जूझ रहे हो तो डॉक्टर से सलाह लेने के साथ ही अपनी डाइट में सुधार करना चाहिए। सेलिब्रिटी डायटीशियन रुजुता दिवेकर से हीमोग्लोबिन बूस्ट करने के 7 तरीके जानें।

एनीमिया यानी शरीर में हीमोग्लोबिन (रेड ब्लड सेल्स) की कमी होना। इसकी वजह होती है पोषण की कमी। खासतौर पर आयरन और विटामिन बी12 कम होने से हीमोग्लोबिन के प्रोडक्शन में बाधा आ सकती है। महिलाओं में ये समस्या ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि वह हर मंथ पीरियड से गुजरती हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी, मेनोपॉज जैसे फेज भी होते हैं। खून की कमी में चिड़चिड़ापन होना, बाल झड़ने लगना, पीरियड्स में दिक्कत आना, त्वचा का बेजान हो जाना, थकान, हार्टबीट अचानक बढ़ना जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर अलग-अलग तरह के फूड्स को डाइट का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हीमोग्लोबिन के स्तर में सुधार किया जा सके।

करीना कपूर की डायटीशियन रुजुता दिवेकर अक्सर हेल्दी रहने के लिए खानपान से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां देती रहती हैं। उन्हें कई बड़े सेलिब्रिटी जैसे नीना गुप्ता से लेकर सोनम कपूर तक फॉलो करते हैं। उन्होंने शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के 7 आसान तरीके बताएं हैं, जिन्हें आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं।

हर रोज 1 फ्रेश फ्रूट

रुजुता दिवेकर कहती हैं कि हीमोग्लोबिन लेवल सुधारने के लिए रोजाना एक फ्रेश फ्रूट खाएं। इस वक्त गर्मी है तो आप आम खा सकते हैं। इसके अलावा अमरूद और काजू का फल भी विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स हैं। विटामिन सी आपके शरीर में जब अच्छी तरह से पहुंचता है तो ये आयरन को सही से ऑब्जर्व कर पाता है।

पल्सेस और लैग्यूम

डायटीशियन ने हीमोग्लोबिन बूस्ट करने का दूसरा तरीका बताया है कि आप दाल और लैग्यूम यानी फली वाली चीजों जैसे अरहर, कुलैथ, राजमा, मटर चना को डाइट का हिस्सा बनाएं। इससे आपको अमीनो एसिड्स, फाइबर और विटामिन बी मिलता है। इससे भी आयरन अब्सॉर्प्शन इंप्रूव होता है। इन चीजों का सेवन भाकरी, चपाती या फिर चावलों के साथ ही करें।

दही-छाछ और लस्सी

रुजुता दिवेकर कहती हैं कि गर्मी का सीजन है तो आपकी हीमोग्लोबिन बूस्ट के लिए तीसरी चीज जो करनी चाहिए वो है दही, छाछ और लस्सी जैसी चीजों का सेवन करना। आप ब्रेकफास्ट या लंच में इसे ले सकते हैं। इससे आपके मील में बी12 बढ़ता है। इससे भी आयरन अब्सॉर्प्शन बढ़ता है जो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन के लिए जरूरी है।

चना-गुड़ खाएं

भारत में चना गुड़ का कॉम्बिनेशन काफी पुराना है। इसे लोग अब काफी कम खाते हैं, लेकिन ये एक बेहतरीन तरीका है आयरन का अब्सॉर्प्शन बढ़ाने के लिए। तो आप एक सीमित मात्रा में चना-गुड़ का सेवन भी कर सकते हैं।

ऐप्रिकॉट है बेहतरीन सोर्स

शरीर में हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने के लिए डायटीशियन रुजुता दिवेकर ने एक फल के बारे में और भी जिक्र किया है और वो है ऐप्रिकॉट यानी खुबानी। ये भी समर सीजन का फल है जिसे आप इस मौसम में फ्रेश खा सकते हैं तो वहीं ड्राई फ्रूट के रूप में भी इसे खाया जाता है। ये फल आयरन का बढ़िया सोर्स है। इसे आप रोजाना दिन में 1 बार खा सकते हैं।

हलीम सीड्स के लड्डू

आप अपनी डाइट में हलीम सीड्स को शामिल कर सकते हैं। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे। इसके लड्डू बनाकर खाएं। हलीम सीड्स आयरन का बढ़िया सोर्स है।

कुकिंग में लोहे के बर्तन

शरीर में आयरन इंप्रूव करने के लिए डायटीशियन रुजुता दिवेकर ने सांतवा तरीका बताया है कि आप खाना बनाने के लिए लोहे के बर्तन जैसे तवा, कलछी, कड़ाही का इस्तेमाल करें।

रुजुता दिवेकर कहती हैं कि जब आपके शरीर में आयरन का लेवल सही रहता है तो थायराइड फंक्शन सुधरता है। एनर्जी लेवल इंप्रूव होते हैं। मूड अच्छा रहता है। स्किन की हेल्थ सही रहती है। ओवेरियन फंक्शन भी सही रहता है और बालों की हेल्थ ही अच्छी होती है। वह कहती हैं कि तंबाकू, शराब और सिगरेट आपके आयरन लेवल को कम करती हैं। बहुत ज्यादा ब्लैक कॉफी भी आयरन अब्सॉर्प्शन में रुकावट डालती है और हर रोज जूस, फ्रूटी, स्मूदी जैसी चीजें खाते हैं, लेकिन खाना स्किप करते हैं तो भी आयरन का अब्सॉर्प्शन रुकता है। इसके अलावा लोग एक गलती ये करते हैं कि ढेर सारा सलाद खाकर मील को स्किप कर देते हैं। ये भी न करें।

डायटीशियन की ये बातें भी रखें ध्यान

भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहने के लिए अपनाएं ये 5 आसान तरीके

भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वस्थ रहना एक चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। काम की व्यस्तता और समय की कमी के कारण हम अक्सर अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर देते हैं। हालांकि, कुछ आसान और असरदार तरीके अपनाकर आप अपनी दिनचर्या में स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे सुझाव देंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में भी स्वस्थ रह सकते हैं।

समय पर खाना खाएं

खाने का समय तय करना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि आप हर दिन एक ही समय पर खाना खाएं ताकि आपका पाचन तंत्र सही रहे। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना एक ही समय पर खाएं। इससे आपका शरीर समय पर भोजन के लिए तैयार रहेगा और आप अधिक ऊर्जावान महसूस करेंगे। इसके अलावा यह आदत आपको भूख लगने पर तुरंत कुछ भी खाने से भी रोकेगी और आप स्वस्थ रहेंगे।

पानी पीना न भूलें

भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर लोग पानी पीने का समय नहीं निकाल पाते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत जरूरी है। दिनभर में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीना चाहिए। इससे आपका शरीर तर रहेगा और आप तरोताजा महसूस करेंगे। अगर आप ऑफिस या काम के दौरान व्यस्त रहते हैं तो अपने डेस्क पर एक पानी की बोतल रखें और उसे समय-समय पर भरते रहें। इससे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

थोड़ा समय निकालकर व्यायाम करें

व्यस्तता के कारण व्यायाम करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह बहुत जरूरी है। आप सुबह या शाम किसी भी समय 20-30 मिनट की सैर कर सकते हैं या हल्की-फुल्की कसरत कर सकते हैं, जैसे योग या स्ट्रेचिंग। अगर समय की कमी है, तो लंच ब्रेक में थोड़ी देर टहलें या ऑफिस के पास पार्क में जाकर कुछ मिनट टहलें। इससे आपका शरीर सक्रिय रहेगा और मानसिक तनाव भी कम होगा।

पर्याप्त नींद लें

भागदौड़ भरी जिंदगी में पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि आप हर रात कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें, ताकि आपका शरीर पूरी तरह से आराम कर सके। अगर आप देर रात तक काम करते हैं तो सोने से पहले मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे आपकी नींद प्रभावित होती है। इसके बजाय किताब पढ़ें या ध्यान लगाएं ताकि आपकी नींद अच्छी हो सके।

संतुलित आहार अपनाएं

संतुलित आहार आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। अपनी डाइट में फल, सब्जियां, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट शामिल करें ताकि आपका शरीर सभी जरूरी पोषक तत्व प्राप्त कर सके। जंक फूड से बचें और घर का बना खाना ही खाएं ताकि आपकी सेहत बेहतर बनी रहे। इन सरल उपायों को अपनाकर आप अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में भी स्वस्थ रह सकते हैं। इन आदतों को नियमित रूप से अपनाने पर आपका जीवन खुशहाल और सक्रिय रहेगा।

क्या रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेना है जरूरी

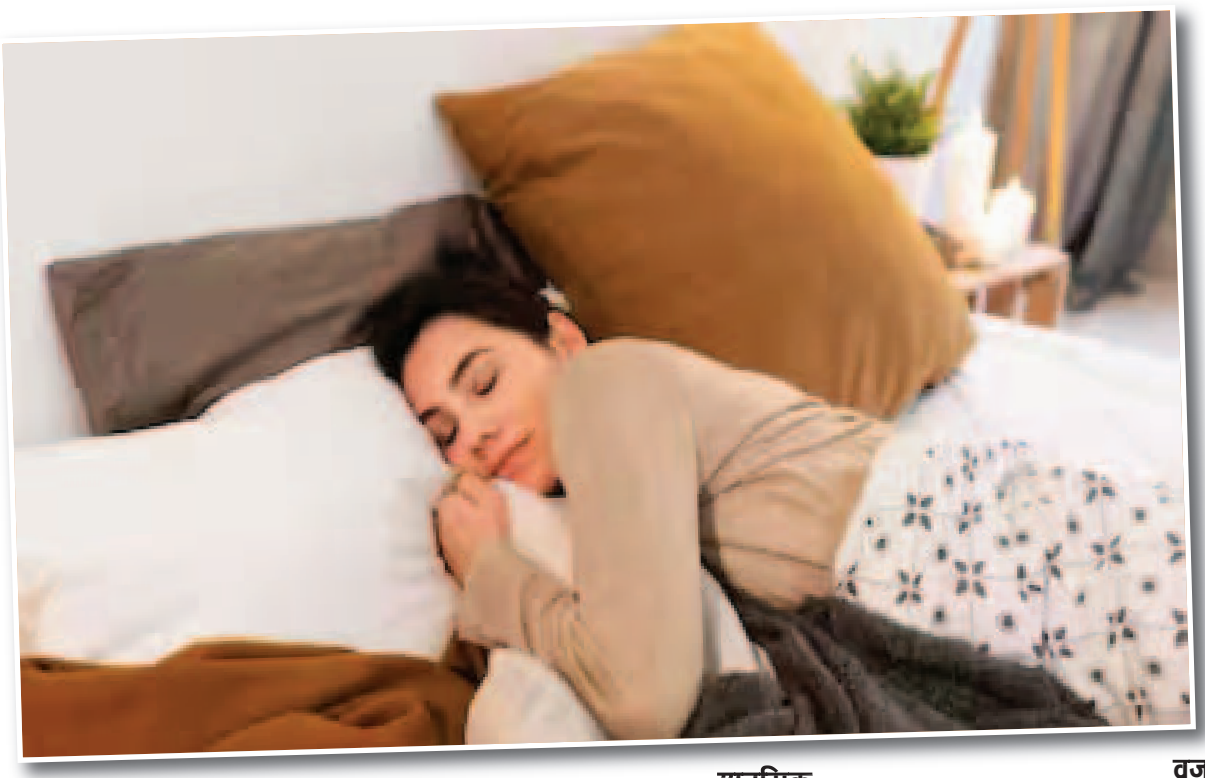

नींद हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। कामकाज या अन्य कारणों की वजह से कई लोग पर्याप्त नींद नहीं ले पाते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेना कितना जरूरी है? यह लेख आपको बताएगा कि क्यों हमें इतनी नींद लेनी चाहिए और इसके क्या फायदे हो सकते हैं। सही मात्रा में नींद लेने से हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं।

मिलती है भरपूर ऊर्जा

पर्याप्त नींद लेने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं, तो हमारा शरीर खुद को ठीक कर पाता है और नई ऊर्जा प्राप्त करता है। इससे हम दिनभर ताजगी महसूस करते हैं और हमारी काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। इसके अलावा अच्छी नींद लेने से हमारा मूड भी बेहतर रहता है, जिससे हम अधिक सकारात्मक महसूस करते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभा पाते हैं।

मानसिक स्वास्थ्य में सुधार

नींद हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालती है। जब हम ठीक से सोते हैं तो हमारा दिमाग बेहतर तरीके से काम करता है। इससे हमारी याददाश्त मजबूत होती है और हम अधिक ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। इसके अलावा अच्छी नींद लेने से तनाव कम होता है और मन शांत रहता है, जिससे हम अपने विचारों को स्पष्टता से समझ पाते हैं। इस तरह पर्याप्त नींद लेने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुधारता है।

रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ाना

पर्याप्त नींद लेने से हमारी रोग से लड़ने की क्षमता भी मजबूत होती है। जब हम अच्छी नींद लेते हैं, तो हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है और हम जल्दी ठीक हो पाते हैं। इससे हम स्वस्थ रहते हैं और सकारात्मक महसूस करते हैं। इस तरह पर्याप्त नींद लेना हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।

वजन संतुलित रखना

पर्याप्त नींद वजन संतुलित रखने में भी मदद करती है। जब हम ठीक से सोते हैं तो हमारी भूख नियंत्रित रहती है और हम अधिक खाने से बचते हैं। इससे हमारा वजन संतुलित रहता है और मोटापे के जोखिम कम होते हैं। इसके अलावा अच्छी नींद लेने से हमारे शरीर की ऊर्जा का स्तर भी बेहतर होता है, जिससे हम अधिक सक्रिय महसूस करते हैं। इस तरह पर्याप्त नींद लेना हमारे समग्र स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है।

लंबे समय तक स्वस्थ रहना

पर्याप्त नींद लेना लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। नियमित रूप से 7-8 घंटे सोने वाले लोग अधिक सक्रिय रहते हैं और उन्हें उम्र संबंधी बीमारियों का खतरा कम होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रोजाना 7-8 घंटे की नींद लेना कितना जरूरी है। इसे नजरअंदाज न करें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं ताकि आप शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों में स्वस्थ रह सकें।

पेटीएम को लगा बड़ा झटका, आरबीआई ने कैंसिल किया पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस, धड़ाम से गिरे शेयर

भारतीय रिजर्व बैंक की एक बड़ी और सख्त कार्रवाई के बाद पेटीएम के निवेशकों में हड़कंप मच गया है। सोमवार को शुरुआती कारोबार में ही वन 97 कम्युनिकेशंस के शेयर औंधे मुंह गिर गए। दरअसल, आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया है। इस कड़े कदम के साथ ही कंपनी की बैंकिंग सेवाओं के दोबारा शुरू होने की बची-खुची उम्मीदें भी अब हमेशा के लिए खत्म हो गई हैं। बाजार खुलते ही मची भारी बिकवाली के चलते पेटीएम का शेयर 1,077 रुपये पर ट्रेड कर रहा था, जो दिन के सबसे निचले स्तर से लगभग 8 प्रतिशत नीचे आ गया।

पाबंदियों के बाद अब सीधा लाइसेंस हुआ रद्द

पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर रिजर्व बैंक की यह सख्ती अचानक नहीं हुई है। जनवरी 2024 से ही इस बैंक पर कई तरह की कड़ी पाबंदियां लागू कर दी गई थीं। पुरानी कार्रवाइयों के तहत बैंक में नए डिपॉजिट लेने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी, जिसके कारण बैंक को अपना कामकाज धीरे-धीरे समेटना पड़ रहा था। लेकिन अब आरबीआई के इस अंतिम और कड़े फैसले ने एक बैंक के रूप में काम करने की इसकी क्षमता को जड़ से खत्म कर दिया है। निवेशकों ने इस रेगुलेटरी कदम पर तुरंत प्रतिक्रिया दी, जिससे शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली।

कंपनी ने दी सफाई, कमाई पर नहीं पड़ेगा असर

लाइसेंस रद्द होने की इस बड़ी खबर और शेयरों में आई गिरावट के बीच पेटीएम की मूल कंपनी ने बयान जारी कर निवेशकों को आश्वस्त करने की कोशिश की है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि आरबीआई के इस ताजा कदम का उनकी मौजूदा कमाई पर कोई खास नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी के मुताबिक, पेमेंट्स बैंक का कारोबार पहले से ही लगभग बंद होने की कगार पर था और अब उन्होंने अपने कामकाज को पूरी तरह से एक पार्टनर-आधारित मॉडल में बदल दिया है। इस रणनीतिक बदलाव के कारण उन्हें वित्तीय मोर्चे पर बड़े नुकसान की आशंका नहीं है।

ब्रोकरेज फर्म 'गोल्डमैन सैक्स' ने घटाया टारगेट प्राइस

पेटीएम पर हुए इस एक्शन के बाद दिग्गज अंतरराष्ट्रीय ब्रोकरेज फर्म गोल्डमैन सैक्स ने भी अपनी राय रखी है। फर्म ने पेटीएम के शेयरों पर अपनी 'बाय' रेटिंग तो बरकरार रखी है, लेकिन इसका टारगेट प्राइस 1,470 रुपये से घटाकर 1,400 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। इसके बावजूद, इस नए टारगेट प्राइस का मतलब है कि पिछली क्लोजिंग कीमत के मुकाबले शेयर में अभी भी लगभग 31 प्रतिशत की बढ़त की गुंजाइश है।

गोल्डमैन सैक्स का मानना है कि बैंकिंग लाइसेंस का रद्द होना निश्चित रूप से एक नकारात्मक घटना है, लेकिन इसका सीधा वित्तीय असर पेटीएम के मुख्य कामकाज पर नहीं पड़ेगा। हालांकि, ब्रोकरेज फर्म ने यह चिंता जरूर जताई है कि इस कदम से ग्राहकों और व्यापारियों के भरोसे को ठेस पहुंच सकती है, जो भविष्य के लिए एक जोखिम है। फर्म का यह भी कहना है कि भले ही यह खबर शेयर पर कुछ समय के लिए दबाव डाले, लेकिन पेटीएम के मुख्य कारोबार की रफ्तार और बुनियादी ढांचा अभी भी मजबूत बना हुआ है।

हर 2 घंटे काम पर 20 मिनट आराम, गर्मी में स्विगी-जोमैटो-फ्लिपकार्ट वालों के लिए सरकार से मांग

घर के लिए ग्रॉसरी आइटम्स लाने हों या फिर कुछ खाने को लाना हो, हम और आप गर्मियों में घर से निकलना नहीं चाहते। ऐसे में हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और मिनटों में सामान हाजिर। बहुतों का ध्यान डिलीवरी ब्वॉय की तरफ नहीं जाता है कि इतनी भीषण गर्मी और धूप को झेलते हुए आप तक पहुंचे हैं। कई बार पानी पूछते हैं और कई बार थोड़ा सुस्ताने को कहते हैं। लेकिन उन्हें तो फिर काम पर निकलना होता है। इन्हीं गिग वर्कर्स के लिए सरकार से सुरक्षा नियमों की मांग की गई है। नियम ऐसे कि हर 2 घंटे के काम के बाद 20 मिनट आराम करने को मिले और इसके पैसे न काटे जाए। और भी कुछ मांगों के साथ सरकार को पत्र लिखा गया है।

जिस तरह गर्मी बढ़ रही है, सड़कों पर काम करने वाले ऐसे लाखों गिग वर्कर्स का स्वास्थ्य खतरे में है। स्विगी, जोमैटो, जेप्टो, ब्लिंकइट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए सरकार से हस्तक्षेप करते हुए पेड कूलिंग ब्रेक और इमरजेंसी सपोर्ट जैसे प्रावधान लागू करने की मांग की गई है। गिग वर्कर्स के एसोसिएशन-IFAT यानी इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-आधारित ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय को पत्र लिखा है और 'कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020' के तहत कड़े सुरक्षा नियम लागू करने की मांग की है।

IFAT के प्रमुख प्रस्ताव

पेड कूलिंग ब्रेकः जब भी IMD ऑरेंज या रेड अलर्ट जारी करे, तो एग्रीगेटर्स हर 2 घंटे के काम पर कम से कम 20 मिनट का 'पेड कूलिंग ब्रेक' प्रदान करें। पेनल्टी से सुरक्षाः गर्मी के कारण काम रोकने या देरी होने पर वर्कर्स की रेटिंग कम न की जाए और न ही उनके 'ID ब्लॉक' किए जाएं। अनिवार्य सुविधाएंः ऐप कंपनियों को पीने के पानी, ORS और कूलिंग सेंटरों (विश्राम स्थलों) का इन-ऐप मैप देना चाहिए। इमरजेंसी सपोर्टः ऐप में 'हीट डिस्ट्रेस' बटन होना चाहिए, जो संकट के समय वर्कर को तुरंत एम्बुलेंस या अस्पताल से जोड़ सके।

सख्त कानूनों की जरूरत

IFAT के राष्ट्रीय महासचिव शेख सलाउद्दीन ने मंत्रालय से आग्रह किया है कि वर्तमान में मौजूद केवल 'सलाहकारी' दिशा-निर्देशों को वैधानिक रूप से अनिवार्य मानकों में बदला जाए। संगठन का कहना है कि डिलीवरी और राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिदम के दबाव में वर्कर्स भीषण लू में भी काम करने को मजबूर हैं।

दूसरे देशों में हैं ऐसे प्रावधान

प्रस्ताव में बताया गया है कि दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देशों ने पहले ही ऐसे कड़े नियम लागू किए हैं, जहां उल्लंघन पर भारी जुर्माने और जेल तक का प्रावधान है। उदाहरण के लिए, दक्षिण कोरिया में 33 डिग्री सेल्सियस तापमान होने पर हर घंटे ब्रेक देना अनिवार्य है।

IFAT का मानना है कि 'हीट प्रोटेक्शन' कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक श्रम अधिकार है और भारत को अपनी डिजिटल इकोनॉमी चलाने वाले इन वर्कर्स की गरिमा और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अब कदम उठाना ही होगा।

साइबर खतरों पर चेतावनी : वित्त मंत्री ने कहा- साइबर हमलों से बचने के लिए वित्तीय क्षेत्र रहे असाधारण रूप से सतर्क

नई दिल्ली, एजेंसी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों और शेयर बाजार से जुड़ी संस्थाओं को साइबर सुरक्षा को लेकर बहुत ज्यादा सावधान रहने की सलाह दी है। सेबी के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब साइबर हमले पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक और तेज हो गए हैं, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा को और मजबूत करना होगा।

वित्त मंत्री ने बताया कि आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई वाले औजारों का इस्तेमाल कर हैकर्स बहुत तेजी से हमले कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने किसी खास कंपनी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा दुनिया के नए और शक्तिशाली एआई सिस्टम (जैसे मिथोस) की तरफ था। उन्होंने कहा कि ये नए सिस्टम खुद-ब-खुद सॉफ्टवेयर की कमियां ढूंढ लेते हैं और सुरक्षा प्रणालियों को चकमा देने में माहिर हैं। सीतारमण ने जोर देकर कहा, हमला करने वाले औजार जितनी तेजी से बदल रहे हैं, हमें अपनी रक्षा करने वाले सिस्टम को उससे भी ज्यादा तेज बनाना होगा।

मंत्री जी ने चेतावनी दी कि अगर किसी बड़े शेयर बाजार या बैंक पर साइबर हमला होता है, तो इससे न केवल लोगों का पैसा डूब सकता है, बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था और जनता के भरोसे को भारी चोट पहुंच सकती है। उन्होंने सेबी से कहा कि वह दुनिया के दूसरे देशों के साथ मिलकर काम करे ताकि भारतीय बाजार सुरक्षित रहें और विदेशी निवेशक भी भारत पर भरोसा कर सकें।

वित्त मंत्री ने कहा कि पूरे देश में एक जैसा केवाईसी सिस्टम होना चाहिए। इससे आम आदमी को हर अलग काम के लिए बार-बार कागजात जमा करने और वेरिफिकेशन कराने की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।

सोशल मीडिया पर नेताओं के नकली वीडियो (डीपफेक) और फर्जी निवेश वाले ऐप्स के जरिए लोगों को ठगा जा रहा है। मंत्री ने सेबी को आदेश दिया कि वे क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापन चलाकर लोगों को जागरूक करें और ऐसे फर्जी विज्ञापनों को तुरंत हटवाएं।

इंटरनेट पर जो लोग बिना लाइसेंस के निवेश की सलाह देकर अपना फायदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

अंत में वित्त मंत्री ने कहा कि बाजार केवल बड़ा होने से काम नहीं चलेगा, उसे ईमानदार और सुरक्षित भी होना चाहिए। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए एसबीआई के चेयरमैन की अध्यक्षता में एक खास कमेटी भी बनाई है।

यूएन में अमेरिका की एक नहीं चली, 121 देशों के समर्थन से ईरान को मिला ये पद

वॉशिंगटन, एजेंसी। संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में परमाणु अप्रसार संधि की एक महीने तक चलने वाली बैठक शुरू हो गई है। बैठक की शुरुआत में 34 देशों के प्रतिनिधियों को उपाध्यक्ष चुना गया। इनमें एक नाम ईरान का भी है। अमेरिका के भारी विरोध के बाद भी ईरान को एनपीटी के भीतर उपाध्यक्ष का पद मिला है। एनपीटी में एक अध्यक्ष और 34 उपाध्यक्ष हर 5 साल पर चुने जाते हैं। अध्यक्ष की कुर्सी इस बार वियतनाम को मिली है, जो चीन और रूस का करीबी माना जाता है।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने इसे रोकने के लिए आखिरी वक्त तक ताकत लगाई, लेकिन 121 देशों के समर्थन से ईरान को यह पद मिल गया। ईरान का कहना है कि उसके नेता ने हमेशा परमाणु का विरोध किया। उसको लेकर पूरी दुनिया में अमेरिका झूठ फैला रहा है।

परमाणु अप्रसार संधि के अध्यक्ष हेंग वियत के मुताबिक गुट निरपेक्ष देशों ने ईरान का समर्थन किया। यूएई और अमेरिका जैसे देशों ने इसका विरोध किया, लेकिन वह कारगर साबित नहीं हो पाया। इसके बाद ईरान को एक उपाध्यक्ष की कुर्सी दी गई है।

अमेरिकी शस्त्र नियंत्रण और अप्रसार ब्यूरो के सहायक सचिव क्रिस्टोफर येव ने अपने एक बयान में इसे एनपीटी के लिए अपमान बताया है। केव के मुताबिक ईरान लंबे समय से परमाणु अप्रसार नीति की प्रतिबद्धताओं के प्रति अपनी अवमानना प्रदर्शित किया है। ऐसे में उसे चुना जाना बेहद शर्मनाक है।

केव ने आगे कहा कि यह कलंक करने वाला फैसला है। इससे एनपीटी की विश्वसनीयता खत्म हो सकती है। दूसरी तरफ अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में ईरान के दूत रजा नजाफी ने अमेरिका की नियत पर सवाल उठाया।

नजाफी ने कहा कि अमेरिका एकमात्र देश है, जिसने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया है। ऐसे में उसे इस पर बोलने का कोई हक नहीं है। नजाफी ने आगे कहा कि अमेरिका अपने परमाणु शस्त्रागार का लगातार विस्तार कर रहा है।

परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी क्या है?

1970 में शीतयुद्ध के दौरान परमाणु हमले के खतरे को देखते हुए इसे बनाया गया था। यूएन की देखरेख में यह संगठन काम करता है। इसका मकसद दुनिया को परमाणु हमले से बचाना है। 190 से ज्यादा देश इसके सदस्य हैं। इस संगठन का 3 मुख्य उद्देश्य है।

1- जिन देशों के पास परमाणु हथियार नहीं है, वो इसे हासिल करने का प्रयास नहीं करेंगे।

2- जिन देशों के पास वर्तमान में परमाणु हथियार है, वो उसे कम करने पर काम करेंगे।

3- परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल सिर्फ बिजली प्रयोग के लिए करेंगे।

फायरिंग की वजह से ट्रंप की पार्टी में खाना नहीं खा पाए थे पत्रकार, 2600 लोगों का वो डिनर शेल्टर होम भेजा गया

वॉशिंगटन, एजेंसी। वॉशिंगटन में हुए व्हाइट हाउस कॉरस्पॉन्डेंट्स डिनर के दौरान फायरिंग की वजह से कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ा। इस कारण करीब 2600 लोगों के लिए तैयार किया गया खाना बिना खाए रह गया। यह कार्यक्रम हिल्टन होटल में हो रहा था, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी मौजूद थे।

फायरिंग उस समय हुई जब डिनर चल रहा था और ट्रंप मंच पर थे। अचानक एक हमलावर ने गोली चला दी, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई की और ट्रंप को सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। इस दौरान एक सीक्रेट सर्विस अधिकारी को गोली लगी, लेकिन वह बुलेटप्रूफ जैकेट की वजह से बच गया। आरोपी को मौके पर ही पकड़ लिया गया।

इस घटना के कारण डिनर पूरी तरह रुक गया और मेहमान खाना नहीं खा पाए। इस डिनर में लॉब्स्टर और स्टेक जैसे महंगे व्यंजन शामिल थे। हर प्लेट की कीमत करीब 350 डॉलर (लगभग 33 हजार रुपये) थी। अब सवाल था कि इतना सारा तैयार खाना क्या किया जाए। हिल्टन होटल ने इसे फेंकने के बजाय जरूरतमंद लोगों को देने का फैसला किया। होटल ने करीब 2600 प्लेट खाना दो शेल्टर होम्स को दान कर दिया, जहां घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाएं और बच्चे रहते हैं। खाने को खराब होने से बचाने के लिए पहले उसे फ्रीज किया गया, ताकि वह लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। इसके बाद इसे शेल्टर होम्स तक पहुंचाया गया।

होटल स्टाफ की तारीफ हुई

CBS न्यूज की व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स वेजिया जियांग ने होटल स्टाफ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद स्टाफ ने पूरी रात काम किया और यह सुनिश्चित किया कि खाना बेकार न जाए, बल्कि जरूरतमंदों तक पहुंचे। होटल के प्रवक्ता ने भी बताया कि वे आमतौर पर ऐसे कार्यक्रमों के बाद बचा हुआ खाना स्थानीय संस्थाओं को दान करते हैं। इस बार भी उन्होंने यही किया। जो खाने की सामग्री इस्तेमाल के लायक नहीं थी, उसे फेंकने के बजाय कंपोस्ट बनाकर खेती के काम में भेज दिया गया।

पाकिस्तान में ऊर्जा संकट : सिर्फ 5-7 दिनों का कच्चा तेल शेष, पेट्रोलियम मंत्री परवेज मलिक ने कबूली लाचारी

वॉशिंगटन, एजेंसी। पड़ोसी देश पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के सबसे भीषण ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ा है। पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने चेताया है कि देश के पास अब केवल पांच से सात दिनों का कच्चा तेल शेष बचा है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और लाल सागर में उपजे संकट ने पाकिस्तान की आपूर्ति श्रृंखला को पूरी तरह तोड़ दिया है। यदि अगले कुछ दिनों में तेल की नई खेप नहीं पहुंचती है, तो देश में परिवहन और उद्योग पूरी तरह ठप हो सकते हैं।

मंत्री मलिक ने भारत की रणनीतिक क्षमता का जिक्र करते हुए अपनी बेबसी जाहिर की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास कोई ठोस ऑयल रिजर्व नहीं है। उन्होंने तुलना करते हुए कहा कि हम भारत की तरह सक्षम नहीं हैं। भारत एक सिग्नेचर करके अपने रिजर्व से 60-70 दिनों का तेल रिलीज कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि यहां बाहरी झटकों को सहने की रत्ती भर भी क्षमता नहीं बची है।

पेट्रोलियम मंत्री ने यह भी कहा कि देश के पास एक दिन का भी अतिरिक्त पेट्रोल भंडार नहीं है। उन्होंने ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव को इस संकट की मुख्य वजह बताया। उनके अनुसार, पश्चिम एशिया में जारी यह युद्ध थमता नहीं दिख रहा है। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी अनिश्चितता पैदा हो गई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तत्काल एक प्रभावी ऊर्जा सुरक्षा योजना की आवश्यकता है, अन्यथा देश पूरी तरह ठप हो सकता है। दूसरी ओर, अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों ने पाकिस्तान की मुश्किलों को दोगुना कर दिया है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने साफ कर दिया है कि वे रूसी और ईरानी तेल पर दी गई छूट की अवधि को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बेसेंट ने कहा कि ईरान के लिए अब कोई रियायत नहीं होगी। अमेरिका ने प्रभावी रूप से नाकाबंदी कर रखी है, जिससे ईरानी तेल की आपूर्ति रुक गई है। रूस से तेल खरीद पर मिलने वाली छूट भी खत्म होने वाली है।

रिफाइनरियों के बंद होने का खतरा

इन वैश्विक प्रतिबंधों और घरेलू भंडारण की कमी ने पाकिस्तान को दोतरफा संकट में फंसा दिया है। कच्चे तेल की कमी से रिफाइनरियों के बंद होने का खतरा है। यदि जल्द ही आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की गई, तो पाकिस्तान में परिवहन और बिजली व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो सकती है। सरकार अब भंडारण क्षमता को मजबूत करने के लिए संघर्ष कर रही है, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण यह राह बेहद कठिन नजर आ रही है।

अमेरिका में हिंदू मंदिरों को खतरों से बचाने की तैयारी, कांग्रेस ने पेश किया बड़ा बिल, कैसे होगी सुरक्षा?

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों पर हो रहे लगातार हमलों के बीच अमेरिकी कांग्रेस में एक नया प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य हिंदू मंदिरों और अन्य पूजा स्थलों को उत्पीड़न से बचाना है। लॉमेकर्स का कहना है कि अलग-अलग धर्मों के लोगों के लिए खतरे बढ़ रहे हैं। इस प्रस्ताव का नाम 'सेफगार्डिंग एक्सेस टू कांग्रेगेशन्स एंड रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट्स फ्रॉम डिसरप्शन' (सेक्रेड एक्ट) है। इसके तहत किसी भी पूजा स्थल के 100 फीट के दायरे में लोगों को डराना, रास्ता रोकना या परेशान करना संघीय अपराध माना जाएगा।

इस प्रस्ताव को टॉम सुओजी ने पेश किया था और मैक्स मिलर ने इसमें उनका साथ दिया। सुओजी ने कहा कि किसी को भी परेशान होने या डराए-धमकाए जाने का हकदार नहीं होना चाहिए, खासकर तब जब वे अपने पूजा स्थल की ओर जा रहे हों। वहीं, मिलर ने कहा कि हर अमेरिकी को बिना किसी डर, धमकी या उत्पीड़न के अपने धर्म का पालन करने का हक है।

अमेरिका में धार्मिक जगहों पर बढ़ते हमले

बता दें अमेरिकी कांग्रेस का यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब धार्मिक स्थलों के आसपास हमलों और डराने-धमकाने की घटनाओं को लेकर चिंता बढ़ रही है। समर्थकों का कहना है कि हिंदू मंदिर, यहूदी प्रार्थना स्थल, मस्जिद और चर्च- सभी इस तरह की घटनाओं का सामना कर रहे हैं। 'हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन' ने कहा कि पूरे अमेरिका में हिंदू मंदिरों को निशाना बनाने और उन्हें अपवित्र करने की घटनाओं में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है, जिससे श्रद्धालुओं में असुरक्षा की भावना पैदा हुई है।

इस कानून में क्या-क्या होगा?

ऐसे में इस कानून के तहत अगर कोई पहली बार दोषी पाया जाता है, तो उसे जुर्माना या एक साल तक की जेल हो सकती है। अगर वही व्यक्ति दोबारा ऐसा करता है, तो सजा और सख्त हो सकती है, जिसमें तीन साल तक की जेल भी शामिल है। यह बिल पीड़ितों को दीवानी (सिविल) मामले दर्ज करने का अधिकार भी देता है। इसके अलावा अमेरिका के अटॉर्नी जनरल समेत अधिकारी ऐसे मामलों में रोक लगाने और मुआवजा दिलाने के लिए कदम उठा सकते हैं।

बिल को मिला कई संगठनों का समर्थन

गौरतलब है कि इस बिल को कई संगठनों का समर्थन मिला है, जिनमें 'एंटी-डेफेमेशन लीग', 'अमेरिकन ज्यूइश कमेटी' और 'इस्लामिक सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका' शामिल हैं। एंटी-डिफेमेशन लीग के अनुसार, यहूदियों के खिलाफ नफरत की घटनाएं बढ़ रही हैं। साल 2024 में ऐसी 9,354 घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 1,702 घटनाएं यहूदी संस्थानों में हुईं। अमेरिकन ज्यूइश कमेटी की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 55 प्रतिशत यहूदियों ने डर के कारण अपनी दिनचर्या में बदलाव किया है।

शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर छूट बरकरार

दूसरी ओर इस मामले में समर्थकों का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई खास संघीय कानून नहीं है जो पूजा स्थलों के बाहर लोगों को परेशान किए जाने से बचाए। हालांकि इस बिल में यह भी साफ किया गया है कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार बना रहेगा, जो अमेरिका के संविधान के पहले संशोधन के तहत सुरक्षित है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में घृणा अपराध बढ़े हैं। हिंदू, यहूदी, मुस्लिम और सिख जैसे धार्मिक समुदायों ने अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। कानून बनाने वाले नेताओं का कहना है कि यह प्रस्ताव लोगों की सुरक्षा और उनके संवैधानिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है, क्योंकि देश और दुनिया से जुड़े मुद्दों का असर समाज पर पड़ रहा है।

बंगाल दूसरा चरण: एसआईआर में कटे 12.9 लाख वोटर्स में से 1468 को मिली हरी झंडी

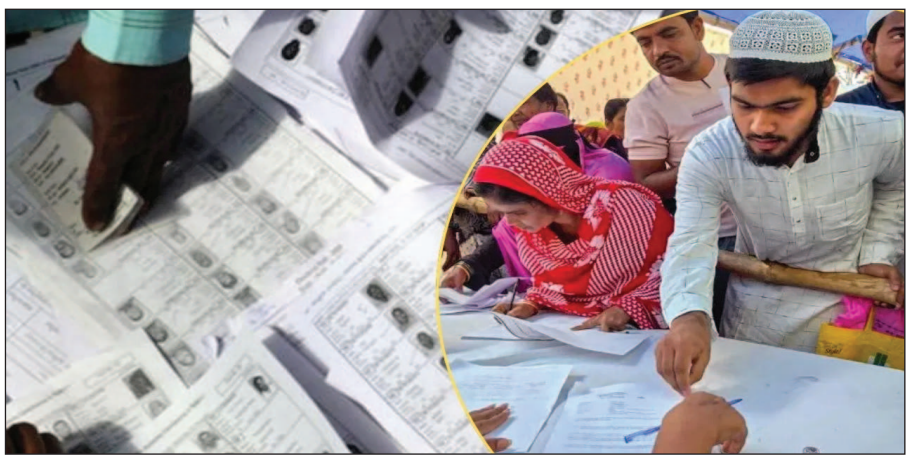

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान आज (29 अप्रैल) को होना है। इससे पहले उन वोटर्स की लिस्ट आ गई है जिनके नाम एसआईआर में कट गए थे, लेकिन उन्होंने ट्रिब्यूनल में अपील की थी। दूसरे चरण के लिए ट्रिब्यूनल ने ऐसे 1468 वोटर्स को जोड़ा है। आयोग की तरफ से जारी किए गए आकंड़ों के मुताबिक, कुल 1474 आवेदनों का रिव्यू किया गया, जिनमें से 1468 वोटरों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया गया है जबकि 6 वोटरों के नाम काट दिए गए। दूसरे चरण के लिए 7 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है जिनमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर में भी शामिल है।

बंगाल में एसआईआर का मुद्दा चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही काफी गर्म रहा। इस प्रक्रिया को लेकर जमकर तकरार भी हुए, और यह अभी तक चल रहा है। पहले चरण का मतदान 23 अप्रैल को हुआ था और उसमें ट्रिब्यूनल की तरफ से 139 वोटर्स को रिव्यू के बाद शामिल किया गया था। पहले चरण के लिए ट्रिब्यूनल की ओर से 657 आवेदनों का रिव्यू किया गया था और उनमें से 139 वोटर्स के नाम जोड़े गए थे। जबकि 8 डिलीट कर दिए गए थे और 518 को 'गलत आवेदन' बताया गया।

दूसरे चरण में 1474 आवेदनों का रिव्यू

इसके बाद दूसरे चरण की वोटिंग के लिए 1474 आवेदनों का रिव्यू किया गया जिनमें 1468 वोटर्स का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया गया, 6 डिलीट किए गए हैं। इसमें गलत आवेदन की संख्या इस बार 0 बताई गई है। हालांकि, इस गलत आवेदन में क्या आधार लिए गए हैं, इसकी आधिकारिक जानकारी आयोग की तरफ से अभी तक नहीं मिली है। दूसरे चरण के तहत पश्चिम बंगाल में 7 जिलों की 142 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं और इन क्षेत्रों में न्यायिक जांच प्रक्रिया के दौरान 12,87,622 वोटर्स के नाम काट दिए गए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, SIR ट्रिब्यूनल ने आज फाइनल वोटर लिस्ट जारी किया, और अब इन्हें सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। पहले चरण की तुलना में इस बार शामिल किए गए वोटर्स की संख्या अधिक है। पहले चरण वोटर लिस्ट में सिर्फ 139 नाम ही जोड़े गए थे।

वोटर लिस्ट से हटाए गए 90 लाख वोटर्स

पश्चिम बंगाल में SIR प्रक्रिया शुरू से ही चर्चा में रही। इस प्रक्रिया के दौरान पूरे पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से करीब 90 लाख वोटरों के नाम हटा दिए गए, जो कुल वोटर्स का करीब 12% है। इसमें से 60 लाख से अधिक लोगों को गैर-हाजिर या मृत की श्रेणी में रखा गया, जबकि 27 लाख लोगों का मामला ट्रिब्यूनल के सामने पहुंचा। जांच के दौरान पर्यवेक्षकों ने पाया कि जिन लोगों का स्टेटस तय नहीं हो पाया था, उनमें से करीब 65% मुस्लिम थे, जबकि दलित हिंदू खासकर मतुआ समुदाय के लोग भी कुछ जिलों में काफी प्रभावित हुए। पहले चरण में, जिसमें 152 विधानसभा सीटों में 23 अप्रैल को वोट डाले गए।

राज्य में 34 लाख से अधिक मामले दर्ज

सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को, संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, चुनाव आयोग को सप्लीमेंट्री वोटर लिस्ट जारी करने का निर्देश दिया, ताकि SIR ट्रिब्यूनल से मंजूरी पाने वाले वोटर्स अपना वोट डाल सकें। कोर्ट ने फैसला दिया कि जिन लोगों की अपील पर 21 अप्रैल और 27 अप्रैल से पहले फैसला हो गया, वे क्रमशः पहले और दूसरे चरण में वोट डालने के हकदार होंगे। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ किया कि सिर्फ अपीलीय ट्रिब्यूनल के सामने अपील पेंडिंग होने की वजह से किसी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार नहीं मिल जाता, राज्य में 34 लाख से अधिक अपील दायर की गई थीं जिसमें गलत तरीके से नाम हटाए जाने से जुड़े मामलों के अलावा उन लोगों की ओर से भी आपत्ति जताई गई थी जिन्हें संशोधित वोटर लिस्ट में कुछ लोगों के नाम शामिल किए जाने पर आपत्ति थी।

'बंगाल में बांग्ला तो महाराष्ट्र में मराठी से दिक्कत क्यों?' टैक्सी चालकों के भाषा विवाद पर राउत

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र में ऑटो और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा को अनिवार्य किए जाने के मुद्दे पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। इसी बीच अब इस मामले में शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह नियम किसी एक राज्य के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश में स्थानीय भाषा के सम्मान के लिए होना चाहिए। राउत ने कहा कि जैसे पश्चिम बंगाल में बांग्ला, गुजरात में गुजराती, कर्नाटक में कन्नड़ और पंजाब में पंजाबी भाषा जरूरी है, तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा को अनिवार्य किए जाने से दिक्कत क्यों?

उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र में स्थानीय भाषा को जरूरी बनाया जा रहा है तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उनके अनुसार, कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के कारण मराठी भाषा का विरोध कर रहे हैं, जो सही नहीं है। संजय राउत ने यह भी कहा कि यह नियम ड्राइवरों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके अपने फायदे के लिए है। अपने बयान में राउत ने इस बात पर जोर दिया कि अगर ऑटो और टैक्सी चालक मराठी भाषा समझेंगे तो उन्हें स्थानीय लोगों से बातचीत करने और काम करने में आसानी होगी।

बता दें कि ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बीते 14 अप्रैल को महाराष्ट्र में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की गुणवत्ता और यात्रियों की सुविधा को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने मंगलवार को घोषणा की थी कि 1 मई, महाराष्ट्र दिवस से सभी लाइसेंस प्राप्त रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य होगा। मंत्री सरनाईक ने आगे बताया था कि मोटर परिवहन विभाग के 59 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से एक लाइसेंस निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान यह सत्यापित किया जाएगा कि संबंधित चालक मराठी पढ़ और लिख सकते हैं या नहीं। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो चालक मराठी नहीं जानते, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।

द केरला स्टोरी 2 की ओटीटी रिलीज डेट बदली, अब फिल्म 8 की जगह 1 मई को जी 5 पर देगी दस्तक

द केरला स्टोरी 2 काफी विवादों में रही थी। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अब फिल्म ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। हालांकि, फिल्म की रिलीज डेट अब चेंज हो गई है।

पहले फिल्म 8 मई 2026 को जी 5 पर रिलीज होने वाली थी। लेकिन अब फिल्म की रिलीज को प्री-पोन कर दिया गया है। अब फिल्म 8 की जगह 1 मई को रिलीज होगी। फिल्म को आप हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगू, मलयालम और तमिल में भी देख पाएंगे।

फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म ने दुनियाभर में 62।353 करोड़ कमाए। वहीं ग्रॉस 52।94 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म ने 88 लाख रुपये से ओपनिंग की थी। इसके बाद पहले हफ्ते में 22।90 करोड़ का कलेक्शन किया। दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 17।35 करोड़ की कमाई की। तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 11।13 करोड़ कमाए। चौथे हफ्ते में फिल्म ने 88 लाख कमाए। पांचवें हफ्ते में ये घटकर 31 लाख हो गया। छठे हफ्ते में 17 लाख का बिजनेस किया। सातवें हफ्ते में 12 लाख और आठवें हफ्ते में 6 लाख कमाए। फिल्म ने नेट 52। 94 करोड़ का कलेक्शन किया।

फिल्म को कामाख्या नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया। विपुल शाह फिल्म के प्रोड्यूसर थे। फिल्म में अदिती भाटिया, उल्का भाटिया, ऐश्वर्या ओझा, अर्जुन ओजला जैसे स्टार्स थे। ये फिल्म अपने कंटेंट की वजह से विवादों में रही। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे कुछ लड़के लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर उनका धर्म बदलवाते हैं और उन पर जुल्म करते हैं।

ये फिल्म 2023 में आई फिल्म का सीक्वल है। द केरला स्टोरी को बहुत पसंद किया गया था। फिल्म ने धमाकेदार कमाई की और फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी। इस फिल्म में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इदनानी और सोनिया बलानी जैसी एक्ट्रेस थीं।

गुलाबी साड़ी और घुंघराले बाल में कविता कौशिक ने बढ़ाई फैंस की धड़कनें

टीवी एक्ट्रेस कविता कौशिक एक बार फिर अपने देसी और नैचुरल अंदाज से फैंस का दिल जीत रही हैं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनका सादगी भरा लुक छा गया है। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने लिखा, बिना किसी एडिट और बिना फिल्टर की तस्वीरें।।। एक्सेंट्स की देवी अगले के लिए तैयार हो रही है।।। मां के घर के करीब।।। क्या आप जानते हैं कि मैं आधी बंगाली हूं और मेरी बंगाली, हरियाणवी और पंजाबी से अच्छी है? बहुत ज्यादा उत्साहित हूं, आगे और देखने के लिए जुड़े रहें।

इसमें कविता ने हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी है, जो बहुत सॉफ्ट और एलिगेंट लग रही है। साथ ही उनका पूरा लुक सिंपल होने के बावजूद बहुत अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। कविता ने ब्राइट पिंक कलर का ब्लाउज कैरी किया है, जिसका डीप नेक डिजाइन उनके लुक को बोल्ड टच दे रहा है। इस फोटो उन्होंने अपने बालों को नेचुरल और खुला रखा है। लंबे और घने बाल उनके पूरे लुक को और खूबसूरत बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने सिल्वर ज्वेलरी पहनी है और उन्होंने अपने लुक को झुमके, कंगन और रिंग्स से पूरा किया हैं। तस्वीरों में उनका मेकअप बहुत ही मिनिमल है, जिससे उनकी नेचुरल ब्यूटी दिख रही है। हल्का काजल और न्यूड लिप्स उनके चेहरे को खूबसूरत बना रहा हैं। बता दें कि कविता ने 2001 में कुटुंब सीरियल से टीवी पर कदम रखा था, हालांकि उन्हें असली पहचान 2006 के एफआईआर में चंद्रमुखी चौटाला के किरदार से मिली। टीवी सीरियल्स के अलावा उन्होंने हिंदी और पंजाबी में कई फिल्मों में काम किया है। उन्हें आखिरी बार साकिब सलीम की सीरीज कप्तान में देखा गया था।

'निगेटिव पीआर बॉलीवुड में चरम पर है', नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोले- फिल्म का प्रमोशन न करना हो, तो मैं दिखूं भी ना

अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने बॉलीवुड में चल रहे निगेटिव पेड पीआर की जमकर आलोचना की। जानिए उन्होंने क्यों कहा कि लोग पैसे देकर खुद को अच्छा एक्टर कहलाते हैं...

बॉलीवुड में पीआर कल्चर काफी बढ़ गया है। इसके साथ ही पैसे देकर किसी के खिलाफ निगेटिव पीआर इन दिनों एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इस बारे में कई कलाकारों ने खुलकर बात की। करण जौहर ने तो पेड पीआर को बंद करने की अपील भी की। अब अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पेड निगेटिव पीआर को लेकर बात की है। नवाज का कहना है कि मौजूदा दौर एक चरम स्तर पर पहुंच गया है, जहां बॉट्स, झूठी कहानियां और मनगढ़ंत राय जनता की सोच को प्रभावित कर रही हैं। आज के दौर में कई चीजें एक अभिनेता के कंट्रोल से बाहर हैं।

मेरा काम सिर्फ फिल्म पर काम करना और मेहनत करना

जूम के साथ बातचीत में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने निगेटिव पीआर और पीआर कल्चर को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि एक अभिनेता के कंट्रोल में केवल एक ही चीज है और वो है अच्छा प्रदर्शन करना। प्रदर्शन कितना आगे जाएगा, यह उनके हाथ में नहीं है। फिल्म के प्रमोशन के बारे में उन्होंने कहा कि अगर प्रमोशन न होता तो लोग उन्हें असल जिंदगी में देख भी नहीं पाते, क्योंकि वे एकांत में रहना पसंद करते हैं। मेरा काम सिर्फ फिल्म को अपना पूरा प्रयास, मेहनत, एकाग्रता और ध्यान देना है। एक बार ये सबकुछ हो जाने पर मेरा काम खत्म हो जाता है।

यह एक बुरा समय चल रहा है

निगेटिव पीआर कंपेन को लेकर नवाज ने कहा कि यह दौर अपने चरम पर है। अभी बहुत कुछ देखना बाकी है और वह भी इसी दौर में होगा। इसलिए यह एक अजीब दुनिया है। मुझे लगता है कि यह कुछ समय तक ऐसे ही रहेगा। उसके बाद कहते हैं कि जब बुरा समय आता है, तो हर चीज के लिए बुरा समय होता है।

क्रिएटिविटी के लिए भी बुरा समय है। हर चीज के लिए बुरा। शायद कुछ साल के बाद अच्छा समय आएगा। लोग बिना किसी अर्थहीन नफरत के सही चीजों को पहचानने लगेंगे। कुछ साल बाद लोग खुद ही समझ जाएंगे कि कौन क्या है, क्या सच है, क्या झूठ है?

मुझे नहीं पता था कि यह दौर लोगों के लिए इतना घटिया हो जाएगा कि अगर मैं दस लोगों को पैसे दूं और उनसे कहूं कि वह एक अच्छा अभिनेता है, तो लोग इस पर विश्वास करने लगेंगे। उनकी अपनी शिक्षा कहां गई? उनकी समझने की क्षमता कहां चली गई?

हां, अगर मैं दस लोगों को पैसे दूं और उनसे कहूं कि आप बहुत अच्छे हैं, तो ग्यारहवां व्यक्ति खुद ही यह कह देगा। मेरे जैसे अभिनेताओं में एक अलग तरह का आत्मविश्वास होता है।

'मैं एक्टर नहीं हूं' में नजर आएंगे नवाजुद्दीन

वर्कफ्रंट की बात करें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी जल्द ही आगामी फिल्म 'मैं एक्टर नहीं हूं' में नजर आएंगे। वो आखिरी बार पिछले साल आई फिल्म 'थामा' में नजर आए थे। इस फिल्म में उन्होंने निगेटिव भूमिका निभाई थी।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित। शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा। RNI No: UPHIN/2014/57034 Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय सम्पर्क: 9839909595, 8765295384 Email: aryavartkrantidainik@gmail.com